साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9300755803, 9425125569
Phone Fax: +91 731 2530859

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 4 अंक 44 | प्रति सोमवार इंदौर, 9 मई से 15 मई 2011 | पृष्ठ 8 | मूल्य 2/- रुपए

अमेरिका-चुनावी छल, नकली लादेन को मारा

महानता की नौटंकी लादेन की मौत

असली तो सितम्बर 2006 में कैंसर से मरा, आतंकवाद के व्यवसाय और हथियार बेचनें की अमेरिकी मुद्रा था, मरने के 5 वर्ष बाद तक भुनाया

अमेरिकी सीआईए और फौज ने नकली लादेन को मारने और विश्व भर में वाहवाहीं लुटने का जो नाटक किया वैसे तो वह किसी भी समझदार के गले नहीं उतर रहा, चूंकि असली ताला ओसामा के सिर के और दाडी के बाल सफेद हो चुके थे, जिसे ये जालसाज से मारना बता रहे हैं। उसकी उम्र मात्र 30-35 वर्ष थी जो उसकी मृत्यु की फोटों से झलका और सिर और दाडी के बाल काले थे, जिस नौटंकी को अमेरिका का मई 2010 से शुह्व होना बता रहा हैं। अमेरिका इस नौटंकी के षडयंत्र को मई 2०1० से उसकी दाडी बढाने असली ओसामा की शक्लओं सुरत में आ जाये तब तक अमेरिकी की राष्ट्रपति के चुनाव की तैयारयां भी शुरु हो जाएगी। चुनाव जितने के लिए इससे बडा और बढिया हथकंडा क्या हो सकता था अमेरिकी जनता के सिर चढकर बोलने और चुनाव जीतने के साथ ही दुनिया पर अपनी दादागिरी महानता सिद्ध करने के लिये सन् 2006 के बाद से जब-जब अमेरिका ने ओसामा के विडियों और टेपस दुनिया के मीडिया पर दिखाये, तब हमारी समय की साइटों ने केवल एक लाइन में ओबामा ने ओसामा को पुर्न जीवित कर अपना आतंकवाद व्यवसाय और हथियारों का बाजार गर्म किया लिखकर अमेरिकी राष्ट्रपति सन् 2008 तक अमेरिकी राष्ट्रपति बुश की। कर्मेन्ट्स व्हाइटहाऊस पर और बुश के जाने के बाद ओबामा के इमेल लिखकर भी दुनिया के मीडिया के ईमेल पर भेजने के साथ पिछलें 5 वर्ष से भेजने के कारण, अमेरिका उसे चुपचाप हर बार 6-8 महीने के लिए उसकी तोरा-बोरा की पहाडियों में बनी क्रब में सुला दिया करता था। फ्रांस के मीडिया के अनुसार ओसामा बिन लादेन सन् ०4 से लीवर केंसर से पीडित था और उसकी मौत सि.06 में ही अफगानिस्तान में ही तोरा-बोरा की पहाडियों के बंकर में ही हो गयी थी, यह बात अमेरिकी प्रशासन के साथ नारों और उच्चस्तर पर अधिकांश राष्ट्रों के राष्ट्रा को मालूम थी, परंतु अमेरिकी प्रशासन और मिडिया ने तो इसे अपना हथियार बेंचने और आतंकवाद के व्यवसाय का आइकॉन बना रख था, साथ ही तो इसकी मौत का भरपूर फायदा उङ्गाने और और नगदीकरण की तैयारी में पिछलें 5 वर्षों से बैङ्गा था। पूर्व का अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने सन् 2004 के चुनाव में इसे टेप का उपयोग कर ही चुनाव दूसरी बार जीता था, उस समय भी समय माया ने अपनी इन साइटों से अमेरिकी राष्ट्रपति की इस चाल का खुलासा कर दिया था, उस समय तो बुश ने चुनाव जीत लिया था, चूंकि हमने जिस दिन ये टेप ओसामा का मिडिया पर आया था समय माया ने केवल चुनावी शिगुफा लिखकर कुश के ई मेल पर भी पहुंचा दिया था बुश ने अपने भारतीय दौरे में एक प्रेस कांफ्रेस में यह बात अपनी आत्मा की आवाज पर स्वीकार की थी और कहा था, कि बेशक मैने लादेन के धमकी भरे टेप से ही चुनाव जीता था। यदि बुश तीसरी बार चुनाव में खडे होने लायक होते तो इस नाटकीय षडयंत्र को वो ही अंजाम देकर चुनाव जीतते। (शेष पृष्ठ 2 पर)

कमीशन खोर, मनमोहन देखों परमाणु ऊर्जा प्लांटों की त्रासदी

समझ लो जापान से मत बोओ बर्बादी

परमाणु प्लांटों से बर्बादी, चेरनोबिल और फुकुशिमा काफी है

नई दिल्ली। भारत में परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के सव्ज बाग दिखाये गये थे। उसकी सनचाई ह्रस के चेरनो बल जो कि वर्षों पुरानी दुर्घटना थी जिसका असर प्लांट के चारों तरफ हैं। वर्तमान में तत्काल में जापान के फुकुशिमा परमाणु संयत्र की भूकंप से हुई दुर्गाति और हजारों की मौत से भी हमारी नहीं चले हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री मनमोहन जो युरोपीयों एजेंट सोनिया की कठपुतली बन नाचकर राष्ट्र की बर्बादी पर तुला है, देख लेना चाहिए कि परमाणु ऊर्जा क्या और केसी होती हैं। जिसका 10-20 वर्ष नहीं वरन् सैकड़ों वर्षों तक असर समाप्त नहीं होता।

महाभारत में पुराणों के अनुसार हुये शुद्ध में भी परमाणु विस्फोट का प्रयोग किया गया, जिसका असर कुरुक्षेत्र में आज भी विद्यमान हैं, महाभारत के कालखंड की जानकारी इतिहास वेत्ता अभी तक ढंग से निर्धारित नहीं कर पायें हैं। यदि हजार वर्ष भी मान ले जैसा कि समुद्र में द्वारका के अवेशषों से निर्धारित किया गया हैं, पुराण महाभारत से ज्ञात होता है कि कुरु क्षेत्र से 440 दिन अंकेश नहीं हुआ था, जबकि उस काल में विद्युत की कोई कलना तक नहीं थी, परमाणु तिस्फो का खुल कर उपयोग हुआ था, वहां पर सामान्य से कई गुना रेडियों विकिरण वर्तमान में भी हैं।

इसके विपरीत भारत में प्राकृतिक स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन इतना दुष्कर और महंगा भी नहीं है। हां अब यह एक महत्वपूर्ण सत्य बन गया है कि विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्त्रोतों पर राजनेताओं, शासकीय केंद्र औरा राज्य सरकारों में बैठे धूर्तों को इससे मोटी कमाई नियमित रुप से चाहिये, इसकी व्यवस्था में अवश्य सभी जुटे हैं, उसका ही दूसरा ह्रप हैं, परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन कर हर कदम वसूली की बड़ी और मोटी समातनायें, क्योंकि सभी कुछ आयात करना पड़ेगा। जिसमें हर कदम मोटा कमीशन हर किसी को मिलेगा, फिर परमाणु ईधन के आयात पर जीवन भर मोटा कमीशन उकारा जाता रहेगा।

राष्ट्र को भले ही परमाणु की ऊर्जा की जह्वरत भी हो परंतु सारे हरामखोर डकैत सत्ताधीशों को दीर्घ काल तक कमीशन जो अरबों रु. में होगा उसकी दूसरी और विदेशों खासतौर पर अमेरिका, फ्रांस, आस्ट्रेलिया और अन्य युरापीय राष्ट्रों में उनके परमाणु ऊर्जा संयंत्रों जो कि अपनी पूरी सेवाए दे चुके हैं, समय वांचित हो चुके हैं, उनको नष्ट करने की समस्या से मुक्ति पाने इससे बेहतर क्या उपयोग हो सकता हैं, कि पुनः मत पर भारत को निर्यात कर दिये जायेंगे। स्वाभाविक है यहां बिलर भूकंप आये भी चेरनो बिल ह्रस और फुकुशिया जापान जैसी घटनायें थोड़ी सी भी लापरवाहीं के चलते घट जयेंगी, ह्रस और जापान की आबादी कम होने के साथ हीं वहां की नागरिक व्यवस्थायें ज्यादा ङ्कोस, संवेदन शील, तुरंत क्रियाशील होने वाली हैं।

इसके विपरीत भारत में भ्रष्टचार के चलते इन तीनों तथ्यों का घोर आभात हैं, यदि दूर्घटना घटी तो भोपाल गैस कांड जैसा कांड होना कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा, फिर जिम्मेदारी तय करने में भोपाल गैस कांड की तरह यहां भी 25-50 वर्ष लगा दिये जायेंगे। फिर मामला प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ होगा। तो संभवतः ऐसे परमाणु संयंत्रों में वर्षों तक जिम्मेदारी भी तय नहीं की जा सकेंगी। (शेष पृष्ठ 2 पर)

बजट 2011-12 केन्द्रीय और म.प्र. राज्य-झूठे समंकों की बाजीगरी

किसी को मतलब नहीं- आम आदमी की भूख और आंसू से

पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की कठपुतली, किसानों के साथ छलावा

केन्द्रीय सत्ता में बैठी कांग्रेस ने अपना 11-12 का वित्तीय बजट वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी के माध्यम से प्रस्तुत कर मध्यम, निम्न मध्यम वर्गीय गरीबी रेखा से ऊपर वालों के साथ गहरी साजिश की गई हैं। जिसमें भारत की 507 से ज्यादा आबादी आती हैं। 157 गरीबी रेखा से नीचे हैं। गरीबी रेखा से ऊपर वालों को न केवल गैस सिलेंडर रु. 700/ को और मिट्टी का तेल रु. 25/- प्रति लीटर पडेगा, अगल वित्तीय वर्ष में पेट्रोल रु 80/- प्रति लीटर तक बेंचेगी। सरकार, गरीबी रेखा से नीचे वालों को जो नगद अनुदान देने वाली बात है, तो वह 507 से ज्यादा बंदर बांट में सरकारी अधिकारी गैस एजेंसियां ही पी जायेगी दूसरी और गरीबी रेखा से नीचे वालों पास 107 से ज्यादा के पास गैस कनेक्शन ही नहीं है क्योंकि एक सिलेंडर के साथ में 99 प्रतिशत गैस वितरक एजेंसिया रु. 4500/- से 5000/- में नया कनेक्शन दे रही हैं। स्वाभाविक है, अति गरीब के पास गैस कनेक्शन ही नहीं है। जिसके पास कनेक्शन है वह अति गरीब की श्रेणी में नहीं है, तो फिर लाभ किसे मिलेगा।

बजट की सारी कहानी में सरदार मनमोहन और वि.मं. प्रणव मुखर्जी दोनों ने पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय क्रं. का पूरा ख्याल कर ही पूरा बजट तैयार किया, ताकि वो आम जनता जो निम्न मध्यम और उच्च मध्यमवर्गीय को येन-केन प्रकरण हर दृष्टिकोणों से नोच कर पूंजीपतियों, उद्योगपतियों और बहुराष्ट्रीय क्रं. को ही लाभ पहुंचाये, बेशक बजट की कसरत अक्टूबर से ही शुरु हो जाती है, लेन-देन और सारा हिसा बाकेताब इस जनवरी के अंत तक पूरा हो जाती फरवरी के पहले सप्ताह में ही उद्योग पतियों और पूंजीपतियों की इच्छा नुकूल बजट को अंतिम रुप देने के बाद केवल घोषणा शेष रह जाती हैं। मकान भ्रण पूर्णतः कालोनाइजरों की देखरेख में ही तैयार हुआ उसमें भी रु. 15 लाख तक के ग्रहगुणों में जो गरीबों, गरीबी रेख से ऊपर ओर निम्न मध्यम वर्गीय को कोई लाभ नहीं मिलेगा लाभ मिलेगा तो मध्यम वर्गीयों को जो रु 15 से 25 लाख तक ग्रह निवेश चाहते हैं।

130 वस्तुओं पर एवसाइजडयुटी से बजट जो गरीबों और ग्रामीणों को हितकारी बताया जा रहा था, ने वह कसर यहां पूरी कर दी हैं। 130 वस्तुओं पर एवसाइजडयुटी भले ही थोप दी, परंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ के लाभ के लिये कारें, टीवी, एसीडी, मोबइल फ्रिज, सस्ते कर दिये हैं।

आधाभूत क्षेत्र के विकास के लिये 2 लाख 14 हजार करोड का घन किया गया हैं। जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिये रु. 10,343 करोड की व्यवस्था है, अब प्रश्न यह है, कि राष्ट्र के 70000 कि .मी का राजमार्गों में से अधिकांश बीओटी ठेकेदारों को सौंपा दी गई है तो यह रु.10343 करोड बना आपसी बंदर-बांट के लिये हैं। दूसरी और विदेशी निवेश की सीमा 20 से बढकर 25 विलियन डालकर देना अर्थात विदेशी निवेश द्वारा यहां से लाभंश बटोरकर उसके अनुपात में लाभांश को भी बाहर भेजना ही होगा। निश्चित ही रु 20000 करोड का प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना में निवेश ग्रामीण विकास की आधारभूत उन्नति में सहायक होगा,

130 वस्तुओं पर एक्साइज यूट समाप्त कर रु. 4000 करोड एकत्रित करने की योजना हैं। (शेष पृष्ठ 7 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

कानून बहुत से, पर ईमानदार कौन?

हमारे राष्ट्र में राष्ट्रहित में जन आंदोलनों ने जोर पकडना शुरु कर दिया है। ये वर्तमान और भावी पीढी के लिए राष्ट्रहित में एक शुभ संकेत है। 73 वष के श्री अन्ना हजारे ने लोकपाल बिट के लिए जो आंदोलन किया और राष्ट्र की जनता ने उन्हें समर्थन दिया उसने सिद्ध कर दिया कि अब भ्रष्ट शासक ज्यादा दिन तक मनमानी नहीं कर सकते। इसके विपरीत अन्ना हजारे जैसे 73 वर्षीय बुर्जूग शायद इस बात से अनभिज्ञ हैं। कि कानून वाले कितने ईमानदार है? सबसे बहलापूर्ण तथ्य यह है। इस राष्ट्र में सब तो बिकाऊ है। बस खरीद्दार चाहिए हर किसी को।

जब बाबा रामदेव ने इस बात पर अंगुली उठाई कि पांच व्यक्तियों की समीति में पिता-पुत्र शांति भूषण और प्रशांत भूषण को एक साथ क्यों रखा गया तो अन्ना समर्थक ने बाबा रामदेव को ही डांट दिया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 121 करोड की आबादी में लगभग 10 लाख से ज्यादा वकीलों में इन पिता-पुत्र के अतिरिक्त कोई कानूनी ज्ञान का जानकार नहीं है। दूसरी ओर यदि लोकपाल विधायक 15 अगस्त 11 तक पास हो भी गया तो कौन सा इस देश की जनता का बडा भारी भला हो जाने वाला है। अभी जो वर्तमान में राज्यों में भी लोकायुक्त, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, जैसी पूरे राष्ट्र में एजेंसियां बैठी है। उनकी तरफ भी गौर फर्मा लेते या केन्द्र में बैठी केन्द्रिय जांच ब्यूरो, केन्द्रिय सतर्कता आयोग जैसी एजेंसियां जो बैठी है। उनका दुरुपयोग भी देख लेते। जिनका वेतन सरकार की मर्जी से निकलता है। जिनमें उच्चाधिकारयों के स्तर पर कैसे मनपसंद से भ्रष्टाचार पसंद और सरकार उसके मंत्रियों और अधिकारियों को बचाने वाले लोग बैठाए जाते है। केन्द्रिय सतर्कता आयुक्त के रुप में बैठाए गए पीजे थामस के प्रकरण में जनता देख और समझ चुकी है। यदि सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करवा तो पीजे थामस सतर्कता आयुक्त बन ही गए थे। फिर इसके इतर जब सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इंवेन्टीगेशन कहा जाता है वह सरकार की मंशा के अनुरुप प्रकरण बनाती है। बेगुनाहों को भी फंसाती है। गुनाहगारों को बचाती है। यदि सचमुच दोषी सरकार का पसंदीदा है तो न केवल प्रकरण सरकार की मर्जी से बनाती है। फिर फाइल रद्दी के ढेर में रख दी जाती है। जब संबंधित नहीं सुनता है सरकार की तब उसे उस प्रकरण की याद दिलाई जाती है। यदि फिर भी समय में नहीं आता तब सीबीआई को वर्षों बाद अनुमति दी जाती है। यदि फिर भी समझा में नहीं आता तब सीबीआई को वर्षों बाद अनुमति दी जाती है। न्यायालय के प्रकरण लगाने हर दिन अरबों का भ्रष्टाचार पूरे देश में देश की सरकारों की देख-रेख में होता है। चूंकि उसमें सरकार में बैठे मंत्रियों का ही हिस्सा होता है। इसलिए सब चुपचाप होता रहता है। आखिर मंत्रियों, सचिवों पर अरबों रु. हर वर्ष बाहर भेजने के बाद भी फेरा क्यों नहीं लगा?

परमाणु मुद्दे पर जब सरकार को बहुमत पेश करने की बार आई, तो खुले में सांसदों को खरीदा गया। जिन सांसदें ने धन की खरीद फरोख्त की सीडीयां पेश की। टीवी पर मिडिया ने पूरे देश को दिखाया। वीकीलीब्स में भी मामला आया। इसके विपरीत उन सांसदोंको सदन से ही बाहर का रास्ता दिखाया। विकलीबस में ब इ बट सत्र में मामला आया तो प्रधान मंत्री मनमोहन साफ मुकर गए। दुनिया ने देखा। पर देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालुम क्या हुआ था। तब आपने क्या कर लिया।

फिर भी प्रसन्नता की बात है। कि आप का आंदोलन 5 राज्यों में चुनावों के चलते सफल तो हुआ। बेशक मिडिया को ये सफलता हजम नहीं हुई वह आपके जंतर मंतर के रंग मंच से भारतीय आयुर्विज्ञान संसथान है जाना चाहती थी। बढते जनाक्रोश की मुनाना चाहती थी।

ये शुरुआत है। अभी तो हमारों महत्वपूर्ण मद्दें आप जैसे अन्नाओं के इंतजार में है। जैसे सडकों पर टोल टैक्स, फिर भी पेट्रोल और डीजल पर 78 प्रतिशत टेक्स जिसें 34 प्रतिशत केन्द्र का, 38 प्रतिशत राज्यों का, 2प्रतिशत शिक्षा उपकर फिर भी 60 प्रतिशत प्राथमिक माध्यमिक, उच्च शिक्षा भारी महंगी, 2 प्रतिशत उपकर, 2प्रतिशत अन्यउपकर आदि। राज्यों के विद्युत मंडलों का निजीकरण कर सांसदों, आईएएस, अधिकारियों, उद्योगपतियों, पूंजीपतियों की लूट के चलते हर वर्ष में 2 से 3 बार दरों में बढोतर फिर भी अंधेरा, बढता प्रदुषण, राज्यों के प्रदुषण मंडलों द्वारा प्रदुषणकारियों को खुला संरक्षण और वसूलीकर चुप्पी, देश के पर्यावरण और जलवायु की बर्बादी, चीन द्वारा भारतीय सीमों में चौकियां सडकें और सरकार का भयभीत हो, शांति-शांति चिलाना, ओरएनजीसी द्वारा खोदे गए कुंओं का रिलांयस के पास जाना, केयर्न और वेदांता को उडीसा में खनन, सिविल जजेस की परीक्षाओं द्वारा चयन पर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में ठोस नियम और कानूनों के आधार पर चयन के विपरीत शासन की इच्छाएं सर्वोपरि, फिर समरवाल, बाला सुब्रण्यम जेसे विवाद, हजारों मुद्दे है। आप के कारवां में शामिल हो सके है। आम आदमी, क्योंकि उसे घर में बैठे बीबी, बच्चों की भूख, शिक्षा, आशियाने की व्यवस्था में उलझना पडता है। पर याद रखें कि कानून बनवाने से ज्यादा कानूनों का पान कम से कम 50 प्रतिशत ईमानदारी से हो।

भ्रष्टों और जालसाजों को संरक्षण लोनिवि में प्र.अ.

शैलेन्द्र शुक्ला अगले विस्तार की तैयारी में

महा भ्रष्ट हैं मुख्यमंत्री, मु.सचिव, प्र.सचिव, भ्रष्ट कठपुतली बने

म.प्र. में मुख्यमंत्री शि.रा.सि. चौहान अपने आप को अपने मुंह से मिट्ठनियां बनकर अपनी और अपनी सरकार की किसी भी प्रशंसा करें और प्रशंसा के मीडिया हत्य और श्रव्य को अरबों रु. के जनध्न से विज्ञापन छप बाये और सच्चाई पर पर्दा डालकर उनका मुंह बंद करवाये, इसके विपरीत सत्यताचारों तरफ उनके कुकर्मों से प्रदर्शित हो रही हैं।

मु.मं चौहान, मुख्य सचिव अवनि वैश्य, प्रधान सचिव के के सिंग और सचिव व विवेक अग्रवाल, लोक निर्माण विभाग किने ठींठ है और बेशर्म है। क्योंकि उन्हें वर्तमान प्रभारी प्रमुख अभियंता शैलेन्द्र शुक्ला मोटा कमीशन बांट रहा हैं। इसके चलते उस मेकेनिकल इंजीनियर को एक तो न केवल प्रमुख अभियंता बनाया गया जो 31.05.11 सेवानिवृत्त हो चुका था। इसके विपरीत उसे 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया गया, इसके इस विस्तार का कार्य काल भी 31.05.11 को समाप्त होने वाला हैं। इसके विपरीत यह पुनः नये विस्तार प्राप्त करने की तैयारी में पिछलें 6 माह से लगा हैं, इसके लिये पिछलें साल भर से ही उसने पहले अधीक्षण मुख्य अभियंताओं के पद पर अधीक्षक यंद्धियों के पद पर ऐसे लोगों को बैठाया गया जो केवल इसकी जी हजूरी करें, जैसे तो नचाये के नाचे, जितना पैसा मांगे, जैसे कागजों में हेराफेरी करवाना चाहे तो करें, आंख मींच अधीक्षण यंत्री और मुख्य अभियंता नियमों और कानूनों को बलायेताक रखकर उसकी इच्छानुसार सारी निरीक्षण रिपोर्ट, बजट,प्रशासनिक तकनकी स्वीकृतियां देने के साथ निविदाताओं में हेरफेर, समय विस्तार अधिक लागत भुगतान सब में मोटा कमीशन हर प्रकार के कार्यों को संपन्न किया जा रहा था, पिछलें तीन वर्षों से इसलिए डीपीसी रोकी जा रही थी। अकब चला चाली की बेला में भी इस जालसाज धूर्त ने दैनिक वेतन भोगियों और कार्य भारित कर्मचारियों को न्यायालयों के आदेश पर नियंमित करने से पूर्व हर कर्मचारी से रु. 25000 की मांग की जिससे अधिकारियों ने मांगने और मानने से मना कर दिया तो ये हरामखोर भी उन्हें नियमित करते- करते पलट गया, जबकि उन बेचारे दैनिक वेतन भोगियों ने 25-30 वर्षों से ज्यादा ही सेवायें विभाग को न्यूनतम मजदूरी की दरों पर ही शासन को दी। उनकी जिंदगियां पूरी उन्होंने नियमित होने की आस से गुजार दी। और अब सेवानिवृत्ति की कगार पर पहुंच गये है। दूसरी और इन्हें नियमित करने के पीछें ये शुअरों की फौज सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों के साथ चल करते हुए कि पद रिक्त नहीं है। उनके नियमितीकरण को कई वर्षों से टाला जा रहा है। जबकि 1988 से बाबुओं, चपरासियों, टायपिस्टो, ड्राइवरों की भर्ती नहीं हुई। हर वर्ष सैकड़ों बाबु, चपरासी, टायपिस्ट पूरे प्रदेश में सेवा निवृत्त होते हैं। उनके रिक्त पदों पर न केवल चपरासियों वरन् बाबुओं, टायपिस्टों ड्राइवरों, खलासी, रसोईये, माली की तरह कुशल श्रमिकों को तरह 8 से 12 घंटे काम करने के बाद भी उसने घरों पर भी जोतकर काम लिया जाता है। अन्यथा धमकियां की बाहर निकाल देंगे। घोर शोषण किया जा रहा है। जाति इस पापी को कुछ भलाकर पाप धोने का अवसर मिला था, पर इस घोर भ्रष्ट जिसके अनकों अंकों में खुलासे किये गये हैं। यहां पर भी उन गरीबों से रु. 25000 मांग लिये जिनकी जिंदगी फटेहाली पर समाज में रहने में थिगड़े-थिगड़े गुजर गई। आखिर तो रु. 25000 कहां से लाकर देते, क्योंकि चलाचचली की बेला में जो हाथ लगें लूटों खाओं, उन देवेओं के नियमिती करण रद्दकर दिये गये। अब जब खींचतान कर स्थानीय मुख्य अभियंता बना ही दिये तो उन्हें प्रभार देने से रोका जा रहा है। प्रभारी की व्यवस्था को संभाल रहे है प्रदेश के कई अंचलकों में ताकि स्थायी मुख्य अभियंता ही न बन सकें जो बाद में प्रमुख अभियंता पद के दावेदार हो जायेंगे तो इस हरामखोर को हटना पड़ेगा।

बाल वैश्यावृत्ति चलेगी बाल विवाह नहीं

पृष्ठ 8 का शेष

साथ ही किशोरा वस्था में शादी होने से भावनायें और रिश्तों में स्थाथिल बना रहता हैं। सामान्यतः यह देखा और पाया गया कि किशोरावस्था में होने वाली शादियों में पति-पत्नी के 90 प्रतिशत रिश्ते जीवन पर्यन्त स्थानी, रहें जबकि जैसे-लड़की की उम्र बढ़ती गई और जितनी देर स्थानीय रहें, जबकि जैसे-जैसे लड़की की उम्र बढ़ती और जितनी देर से शादीयां हुई, उतने भारत में भी तलाक के मामलें बढ़ते गये, और स्त्रियां बहुपुरुष गामी होती गयी, इसका सबसे बड़ा दुप्रभाव आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। जिसकी तरफ ये यौन लोलुप नेताओं अधिकारियों पर भले हीन पड़ता हो, पर वास्तविकता में तलाक से दिल ही नहीं दिमाग, परिवार व समाज में न केवल टूटता हैं। वरन तलाक शुदा मॉ-बाप के बच्चे समाज में उपेक्षित, और मानसिक कुंठा से जीवन भर ग्रस्ति रहते हैं। जो भविष्य में ऐसे बच्चों को जघन्य अपराधों की तरफ धकेल देती हैं। जिसे समाज में चारों तरफ देखा जा सकता हैं। इसके विपरीत कम उम्र में शादी के चलते चूंकि पति-पत्नी एक दूसरे के दिलों-दिमाग में 13-14 वर्षों की उम्र में ही से ही रच बस और समा जाने के कारण उन्हें एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना करना भी नहीं सुहाता, स्वाभाविक है तलाक की नौबत ही नहीं आती है। इसके विपरीत जब 12 वर्ष की उम्र से लड़कियां 20-35 वर्ष की उम्र तक 1760 को भेग चुकी होंगी या बहुपुरुष गामी हो चुकी होगी तो 25 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें कभी भी एक पति रूपी पुरुष नहीं मायेगा और पति शादी कर भी ली तो वाद विवाद होने पर रास्ते से कांटा हटाने के लिये या तो वो स्वयं हत्या करेगी, या प्रेमियों के साथ मिलकर अन्यथा भाडे. के हत्यारों का उपयोग कर हत्या तक करवाने से नहीं चूंकेगी इसकी सत्यता आये दिन अखबारों में पढ़ी जा सकती हैं। यहीं कारण है, कि भारत में भी तलाक के मामलों में पिछलें दस वर्षों में भारी तेजी आई है, अब बात में तलाक होने लगे हैं। सबसे ज्यादा तालाक का भुगतान बच्चों को करना होता हैं। यदि बच्चों के जन्म के पूर्व अगर तलाक हो गया है तो भी औरतें बहुपुरुष गामी होने अय्याशी के शौकीन होने और नीरा रांडिया बन जाने में परहेज नहीं नहीं करती, और हमारे राजनीतिक नीच मानसिकता के नेता भी यहीं चाहते है कि हमारे राष्ट्र की हर महिला न केवल नीरा रांडिया बने यान भी तो थाई लैंड अवश्य बन जाये ताकि वे अपनी कौन पूरी कर सकें जहां जाये थे उनके काम कराने के बहाने सबसे पहले उन्हें भोंगे, और फिर काम हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो भी चट्टीयों के संबंध जिंदाबाद यहीं कारण है, कि इन्हें 12 साल की लड़कियों की कच्ची उम्र से उन्हें शादी करने की छूट न देकर उन्हें वैश्या और बहुपुरुष गामी बनाकर आखिर राजनीतिक नारी की मॉ की श्रेष्ठ छवि को क्या और कैसे बर्बाद कर रहा है, जबकि नारी पुरुष की हर रूप में ही मॉ की भूमिका अदा करती हैं। परंतु पति, प्रेमी और ग्राहक के रूप में भी जब पुरुष स्तनपान करता है, और नारी उस भी पुत्र की तरह ही सिर पर हाथ फेरकर अपनी मॉ होने की नियमितका कुछ क्षणें के लिये ही सही यथार्थ का परिचय करवा ही देता है। दूसरी और कोलकत्ता की वैश्याओं ने एक दिन में 125 पुरुषों को भोगा है और औकात की वह एक दिन में ढंग 5-10 स्त्रीयों को भी भोग सकें, फिर जिसे वह 12 वर्ष की उम्र में ही स्वच्छद यौनाचार की तरफ धकेल रहा हैं। भविष्य में कमी के किसी की मॉ बनेगी ही तब उसके बच्चे पूछेंगे की मॉ तेरे कितने पास है या जिनकी मातायें ऐसी स्वच्छंद यौनाचार की शौकीन नहीं है। उनसे पूछों की उन्हें बच्चे कैसे बात में जलील करते हैं। इसलिये बाल वैश्याव्रत्ति से बाल विवाह बेहतर हैं।

महानता की नौटंकी लादेन की मौत

प्रथम पृष्ठ का शेष

अब जबकि ओबामा की अमेरिकी में भयानक मंदी के चलते, बेरोजागरों विश्व बाजार में गिरती सांख, कमजोर होती पकड, सिर पर 2010 में आते चुनाव के लिये कोई करिश्माई धमाका करना आवश्यक था, तो जह्नरी था कि जिसे पूरी दुनिया में अमेरिकी प्रशासन ने आतंक का महानायक की असली नहीं तो नकली की हत्या कर अपना महा नायक एवं सिद्ध कर अपनी महानता सिद्धकर लोगों के दिलों श्रेष्ठता सिद्ध करें।

जबकि जो अमेरिका ने नाटक खेला, उस नाट की रिहसल के साथ पूरा नकली मुठभेड का खेल हमारे देश म.प्र. राजस्थान और उत्तरप्रदेश की पुलिस डाकुओं अपराधियों को बचाने उनके इनाम की राशि हडपने झूठी पदोन्नति पाने के लिये 50 वर्षों से ज्यादा समय से सैकडों बेगुनाहों को ऐसी फर्जी मुठभेडों में हत्या कर पदोन्नतियां लेकर सेवा निवृत्त होते गये हैं। बेशक यह गुण अमेरिकी प्रशासन और नेताओं ने भारत से ही सीखा हैं। हमार कांग्रेसी शूकरों ने ही दाउद जैसे आतंकियों को कराची में और काश्मीर में पाला हैं।

जब-जब हमारे देश के डकैत गिद्ध कांग्रेसियों की फौज भ्रष्टाचार, महंगाई, लूट खसोंट से घिर जाती हैं, तो दाऊद को पाकिस्तान में बोलकर उसके चेलों से कभी मंदिर में कभी दरगाह में कभी ट्रेन में ब्लास्ट करवा कर मिडिया और जनता का मयान परिवर्तित करती हैं, फिर वर्षों तक जांच की नौटंकी की चलती हैं।

फिर जांच के नाम पर हिन्दू साधुओं, साध्वियों यहां तक कि सेना के कर्नल और जवानों तक को फंसा कर सेना में कार्यरत हिन्दूओं का मनोबल तक तोडने से नहीं चूकती, तो फिर ओबामा नकली ओसामा का मारकर चुनाव जीतने की नौटंकी करके क्या नया कर रहा हैं। भारत के कांग्रेसियों में यहीं सब भरा हैं।

समझ लो जापान से मत बोओ बर्बादी

प्रथम पृष्ठ का शेष

फुकुशिमा संयंत्र में जापानी राष्ट्र मत्तों ने जान जोखिम में डालकर उसे सुधारने नियंत्रित करने का पुरजोर प्रयास किया और अभी कर रहे हैं। इसके विपरीत भारत में शायद ही ऐसी स्थिति में सुधार और नियंत्रण की कोशिश करेंगा, यहां तो सारे भगोड़े हैं। सब भाग जायेंगे, बर्बाद होगा महानगर उनकी बला से तसब आंकलन भी प्रधानमंत्री मनमोहन उनकी अम्मा सोनिया जिसके इशारे पर ये खेल हो रहा हैं।

अच्छी तरह से मालूम हैं पर हर जगह यहां मोटे कमीशन के सवाल के साथ ही युरोप शक्ति का प्रदर्शन करना है इस राष्ट्र की जनता को केवल वोट देने वाले जानवर है, उनके मरने जीने से इन्हें क्या फर्क पड़ने वाला हैं। ये तो 5-10 साल में धरती ताग देंगे। भविष्य तो वर्तमान और भावी पीढ़ीयों का होगा।

किशोर वाधवानी की कठपुतली है, मप्र वाणिज्यकर, आयकर, कस्टम व अन्य

रु.300 करोड़ कस्टम की तो आयकर और वाणिज्य कर की कितनी

मिडिया माफिया बनना पडा भारी, जो पकडा 10 प्रतिशत भी नहीं

इंदौर में भारत भर में बिकने वाला शिमला गुटखा, उसकी गरम सिगरेट व 10-12 से ज्यादा अन्य उत्पादों जिसका मालिक महाजाल साज किशोर वाधवानी जिस पर फर.व मार्च में कस्टम व एक्साइज विभाग में छापा मारा और कार्रवाई की। जिसकी मात्रा 11 मशीनें ही कस्टम में पंजीकृत थी ओर पकडे जाने पर लगभग 111 मशीने, सिगरेट बनाने के ब्रांडों की मशीनें और सामग्री पकडी गई थी और न केवल शिमला व अन्य कई ब्रांडों के गुटखों की सामग्री पकडी गई।

किशोर वाधवानी ने ये सब कुद एक दिन में तो इकट्ठा नहीं कर लिया। पिछले 15-20 वर्षों से लगातार वह गुटके का कामकर रहा है, इस सब की कहानी न केवल कस्टम व एक्साइज के अधिकारी वरन् आयकर और मप्र के वाणिज्य के अधिकारी भी जानते है। उसका पैसा वाणिज्य कर में इंदार से लेकर भोपाल तक, कस्टम एक्साइज व आयकर में इंदार भोपाल से लेकर दिल्ली तक अधिकारियों को चलाता है। स्वाभाविक ह कि वह छह मशीनों के पंजीयन करवाकर 111 मशीनों से गुटका बनाकर सभी करों जिसमें कस्टम एक्साइज, आयकर और वाणिज्य कर को प्रतिवर्ष रु.300 से 500 करोड का चूना लगाकर कर चोरी करता है। अब प्रश्न यह उठता है, कि आखिर जब सब पैसा हजर कर रहे थे। तो मामला खुला कैसे। जबकि इंदौर के सभी समाचार पत्रों को भी साल भर में यथा योग्य करोडों के विज्ञापन बांटे जाते थे अधिकांश छूट में ये पत्रकारों को भी महीना बांटा जाता था। इसलिए अखबार वाले भी चुप रहते थे। पर जब किशोर वाधवानी ने दबंग दुनिया छापना शुरु की वैसे ही इंदौरी मीडिया के भुखेरों का समझ आया कि अब यह न तो विज्ञापन देगा और नहीं पत्रकारों को महीना।

दूसरी और कसम एंड एक्साइज के लगभग 10 अधिकरियों को तो ये महीना लाखों रु. में बांट रहा था परंतु लगभग 30 से ज्यादा इसके क्षेत्र के निरीक्षकों अधिकारियों और कर्मचारियों को इसने लगभग 6 महीने से उनकी मासिक रिश्वत का भुगतान नहीं किया था। और न ही भुगतान करने का इसका कोई इरादा था जैसे ही इसने दबंग दुनिया छापना शुरु किया तब ही कस्टम और एक्साइज के उन छोटों को ये अहसास होने लगा कि अब चूंकि ये मिडिया में उतर चूका है अब पैसा कभी नहीं मिलेगा। उल्टा ज्यादा कुछ किया तो ये अपने को ही धमकाएगा और उलझाएगा। इसएि उसकी नाकाबंदी की गई और ऊपर तक शिकायत पहुंचा कर छापे की कार्रवाई की गई जिसमें इंदौरी मिडिया ने पूरा सहयोग किया।

अन्यथा दबंग दुनिया के तीन चार महीने के बाद फिर कोई हाथ लगाने की तो दूर, फिर किशोर वाधवानी के इशारों पर कस्टम एक्साइज के उच्चाधिकारियों से लेकर आयकर और वाणिज्य कर को भी उसी दया पर ही निर्भर करना पडता।

मप्र वाणिज्य कर में भी एक व्यवसायी को एक ही वाणिज्य कर पंजीयन दिया

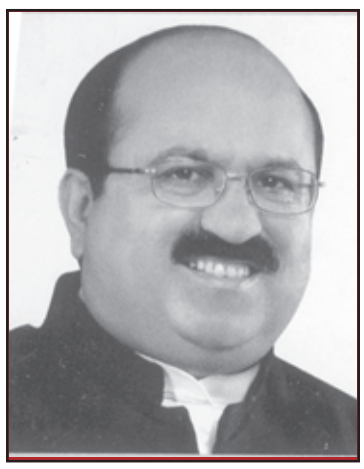

जाता है। इसके विपरीत इसके पास अलग-अलग वाणिज्य कर वृत्तों में कुल मिलाकर 23 पंजीयन इसके पास है। जो कि वाणिज्य कर सहा.वाणिज्य कर अधिकारियों तक सबको मालूम है। स्वाभाविक है यदि सब चुप है तो बिना खाए पिए तो कोई रह नहीं सकता। चूंकि सबको मिल रहा है। इसलिए सब चुप भी है और उसकी कठपुतलियों की तरह उसके इशारे पर नाच भी रहे हैं। उसे अभी सहा. आयुक्त सुनील मिश्रा द्वारा रु.35 लाख का रु. 10 लाख उकार कर आई टीआर भी भुगतान करवाया गया है। यह चर्चा भी वाणिज्य कर के गलियारों में छापों के बाद सुनाई पडी थी। अब जबकि कस्टम ने 6 मशीनों के पंजीयन पर 111 मशीनें चलती पाए जाने पर रु. 300 करोड की ड्यूटी निकाली गई है। स्वाभाविक है उसी अनुपात में आयकर और वाणिज्य कर भी चोरी किया गया। जो पिछले 15 वर्षों से सतत जारी है। जहां से इस जालसाज ने अलग-अलग नामों से वाणिज्य कर पंजीयन लिया है वहां के सभी वाणिज्य कराधिकारी सहायक आयुक्त, उपायुक्त तक को वार्षिक मोटी रकम चोरी के बदले देता है।

अपनी इस वाणिज्यकर चोरी को दबाने/बचाने के लिए पहले वर्षों तक इसने इंदौर कांग्रेसी और भाजपाई नेताओं को करोडों में चंदा भी दिया। इसके साथ ही इसने इस चंदे के बदले दोनों ही पार्टी नेताओं के कार्यक्रमों व अन्य प्रकार के सभी अखबारों में विज्ञापनों में भी अपने बडे-बडे मंत्री और नेताओं के साथ फोटो भी खुब छपवाए। ताकि दोनों में कोई भी एक पार्टी इसे विधायक चुनाव का टिकिट दे दे । परंतु जब-जब इसका नाम आगे बढा, इसकी कारगुजारियों की शिकायत कांग्रेस और भाजपा में भोपाल से लेकर दिल्ली तक भेजी गई। फिर भी विज्ञापनों में छपने से इसने दोनों पार्टियों में दो नं के काले धन का दानदाता के रुप में इसकी बडे नेता आवभगत जरुर करने लगे। इसकी आड में अपनी यह टेक्स चोरी को बचाता रहा कोई भी प्रश्न, इसके किसी भी कारनामें के बारे में न तो विधानसभा में गूंजा न ही अन्य सरकारी विभागों में चूंकि दो नं. के इस अरबों की दौलत की लहर अपने आप को समाजसेवी सिद्ध करने के लिए जैन संत तरुण सागर जी के कार्यक्रमों के विज्ञापनों में भी ये जालसाज जैनियों के धूर्त कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपने फोटो के साथ विज्ञापन छापने और छपवाने में सफल रहा। इसका धन, जमीन, जायदाद के कारोबार के साथ ही आसाराम बापू के कार्यक्रमों में लगाया गया। आसाराम बापू की जालसाजियों, संपत्ति में हुई गिरफ्तारियों में इसने अपने राजनैतिक प्रमाणों का उपयोग कर उसे बचाने में भी भूमिका अदा की।

इसके निकट सूत्रों का कहना है, कि चूंकि इसकी जमावट नीचे से लेकर ऊपर तक है। सबको पैसा बंटता है। इसलिए इसको हर कदम-कदम पर बचाने वाले भ्रष्टों की लंबी श्रृंखला है, जो इसे हर हाल में बचा ही लेंगे। चाहे वह कस्टम हो, आयकर हो, वाणिज्यकर हो। जितना उसका माल और मशीने पकडी गई है। तो उसकी कुल संपत्तियों और धन का 10 प्रतिशत भी नहीं है। अब देखना ये है। कि कौनसा विभाग कितनी कार्रवाई कर सभी करों की चोरी में से कितना वसूल पाता है।

शिमला और किशोर वाधवानी पूरे प्रदेश के ऐसे, सैकडों जालसाज व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके इशारों पर कस्टम आयकर, मप्र वाणिज्यकर के सैकडों अधिकारियों से लेकर सचिव, मंत्री तक नृत्य करते है पूरे भारत में लगभग ऐसे 1 लाख से ज्यादा पूंजीपति है जो सरकारी अमले को हांकते है। ये ही सरकारी केन्द्र और राज्य का उसे करों की चोरी करने के गुर सिखाते हैं। और सलाहकार के रूप में मोटी रकम पाकर उसे बचाते हैं।

बीएसएनएल भ्रष्ट, शूकर, निकंमा लुटेरा

बकवास सेवाएं, अंटशंट बिलिंग, बत्तमीज, निकंमा स्टॉफ

भारत संचार निगम लि. शासकीय क्षेत्र का केन्द्र सरकार का उपक्रम का पर्यायवाची भ्रष्ट, शूकर, निकंमा ओर लुटेरा हो गया है। वैसे भी केन्द्र सरकार के सभी विभागों और उपक्रमों में बैठे अधिकारी राज्य सरकारों के विभागों के अधिकारियों से ज्यादा मोटे भ्रष्ट, महाबेशर्म, महानिकंमें, भारी बत्तमीज, भारी घमंडी कि हम केन्द्र सरकार के कर्मचारी और अधिकारी है, होते है। राज्य सरकार में बैठे अधिकारी, कर्मचारी तो जनता को आंख उठाकर देखकर तरीके से कम से कम बात करते और जवाब दे देते है। पर केन्द्र सरकार के सभी विभागों में तो आयकर, कस्टम, एक्साइज, सरकारी बैंक, सीपी डब्ल्युडी, डाकतार विभाग, रेलवे, भूतल परिवहन, रा.रा. बीमा, प्राधिकरण, बीएसएनएल जैसे पूरे देश के सैकडों विभागों की कहानी है। इन सब तथ्यों की पुष्टि के लिए ज्यादा कुछ नहीं किसी भी विभाग में जाकर देखिए अन्यथा किसी भी विभाग की साइट देख लिजिए कि किस विभाग ने सूचना अधिकार अधि. 05 की धारा 4 उसके उपधारा, अ,ब, के 17 बिन्दुओं की जानकारी यथा कार्यालय का कार्य, उसकी कार्य पद्धति, उसमें बैठे अधिकारियों कर्मचारियों का विवरण, उसकी परिसंपत्तियों, वेतन कार्यक्षेत्र आदि का वितरण अधिनियम के लागू होने के 5 वर्ष बाद भी अभी तक नहीं किया गया। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर बैंकर्स, बीमा कंपनियां, आयकर, कस्टम एंड एक्साइज, बीएसएनएल, आकाशवाणी, रेलवे आदि अधिकांश विभाग जानकारी देने की अपेक्षा अपन होशियारी दिखाते हुए शब्दों का घुमाने फिराने वाला पुड़ा दे देते है। फिर भी पत्रानुसार आवेदक ने पैसे जमाकर भी दिए तो चाही गई जानकारी की अपेक्षा दूसरे अन्य दस्तावेजों की फोटाकॉपी पकडा दी जाती है। चूंकि हर कदम ये सारे हरामखोर, भ्रष्टाचार भी करते है। स्वाभाविक कागजों में जालसाजियां करनी ही पडती है। पूर्व में बीएसएनएल का धूर्त महाप्रबंधक निगम जिसके भ्रष्टाचार में से एक दो के विरुद्ध सीबीआई ने जांच शुरु कर दी थी। वर्तमान में बैठे महाप्रबंधक पियुष खरे भी न केवल महाहरामखोर और जालसाज ने भी सूचना के अधिकार में दिए आवेदनों में अपनी जालसाजी दिखाई थी। स्वाभाविक है, कि जालसाजियां की है। तो जानकारियां कैसे दी जा सकती है। इसलिए केन्द्र सरकार के धुर्त जानबूझकर आवेदनों के जवाब 30 दिन के बाद 30 दिन पूर्व की तारीख में देते है। ताकि समझकर और कानून जानने वाला आवेदक यदि अपील लगाता है तो अपीलीय अधिकारी भी जवाब लटका कर दे। वह भी अनावेदक के पक्ष में ताकि आप अंतिम और दूसरी अपील मुख्य सूचना आयुक्त को भेजे जो 1 से 2 वर्ष में उसका नंबर आए और संबंधित अधिकारी बिना कुछ बताए स्थानांतरित हो जाए। यदि दूसरी और अंतिम अपील के निर्णय में भी यदि आवेदक के पक्ष में फैंसला आ भी जाए। तो भी अनावेदक को जानकारी नहीं देना है। है व्यर्थ पैसा और समय तो जाइए उच्च न्यायालय में प्रकरण लगाइए, और लडिए दो-तीन वर्ष से 5 वर्ष।

दूसरी ओर दिल्ली के संचार मंत्रालय, भारत संचार निगम लि. के मुख्यालय से लेकर नगरों, और गांवों में स्थित इन भ्रष्ट निगम के कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों तक सब निजी टेलिफोन ऑपरेटरों से महीना वसूली करते है। तो जानबूझकर अपने ही लैंडलाईन और मोबाइल उपभोक्ताओं को भरपुर परेशान करते है। जिसके चलते सभी समाचार पत्र आए दिन न केवल बत्तमीजियों को छापते रहते है। साथ ही उपभोक्ता भी लडाई झगडे और प्रदर्शन करते रहते है। इनसे जुडे मंत्री से लेकर नीचे तक हर काम ठेकेदारी परदेकर, ठेकेदारों से मोटा कमीशन उकार रहे है। हर अधिकारी पर केन्द्रिय जांच ब्यूरों को इस अरबों रु. के ठेकेदारों के भुगतान की भी जांच करनी चाहिए।

हालात ये है। कि मप्र और छत्तीसगढ के सेल उपभोक्ताओं को पहले तो कोई सेवा केन्द्र का नंबर दिया ही नहीं जो तुरंत उपभोक्ता की समस्या हल कर सके। जो नंबर दिया है वो लगता नहीं जो तुरंत उपभोक्ता की समस्या हल कर सके। जो नंबर 24365 वह सेवा ढंग से काम नहीं करती। यदि आप 10-25 मिनिट की मेहनत के बाद भी अगर आपरेटर से बात कर पाए तो, आपने अपनी समस्या बता भी दी तो जरुरी नहीं कि आप की समस्या तत्काल तो दूर एक-दो दिन से लेकर 15 दिन में भी हल कर पाए। तो धन्य समझिए अपने भाग्य को। इन हरामखोर डकैतों की लूट का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है। कि पूरे राष्ट्र में अधिकांश कंपनियां 20 पै. 30पै. 40पै. और अधिकतम 50 पै. प्रति मिनिट 1 पै. के दो सेकंड, 3 सेकंड उन्हीं के सेवा के नं. पर संवादों के लिए मुफ्त की सेवा दे रही है। रिलायंस जैसी कंपनियां कुछ प्लानों में रु. 250/- प्रतिमाह के शुल्क पर मुफ्त में पूरे राष्ट्र में बात करने की सेवाएं दे रही है। परंतु ये अभी भी प्रति मिनिट रु. 1.20 वसूल रहे है। इसके साथ ही ये यदि आपके खाते में आधिक्य है तो ये भी 10-12 तक रिंगटोन, कॉलर टोन, डालकर अंटशंट उपभोक्ताओं को लूटते है। रोना फिर वहीं यदि आप बंद करवाना चाहें तो सेवा केन्द्र पूना में संपर्क करिए जो घंटों नहीं मिलेगा। वहां पर भी करोडों रु. प्रतिमाह का ठेका कॉल सेंटर्स को दे रखा है। जिसमें मोटा कमीशन टेंडर स्वीकृति से लेकर भुगतान तक में वसूली की जा रही है। जबकि इस भ्रष्ट शूकर निकंमे लुटेरे के पास भी 50 लाख से ज्यादा ग्राहक है मप्र और छग में। सभी से रु. 50 से 100 भी वसूले गए तो रु. 25-50 करोड की तो ऐसे ही लूट लिए जाते है। इस पर ट्राई का न तो नियंत्रण है। न इस डकैती पर कोई रोकटोक।

जनता से सफेद पोश लूट मची है। लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट।

यही हाल लैंड लाइन नंबरों का है। पाठकों को शायद मालूम नहीं पडा होगा कि अब क्षेत्रीय पूछताछ का कार्य भी मप्र और छग का भोपाल में काल सेंटरों को सौंप दिया गया है। अकेले इंदौर में 40 से ज्यादा स्टॉफ और पूरे मप्र में और छग के नगरीय और ग्रामीण पूछताछ केन्द्रों में लगभग 3000 कर्मचारियों के स्टॉफ को ये हरामखोर अधिकारी वर्ग रु. 75-100 करोड तक वेतन मुफ्त में देगा एक तरफ-दूसरी तरफ ठेकेदार कॉल सेंटर फर्म को रु. 5-10 करोड का भुगतान भी करेगा जिसका भार भी सीधा ही उपभोक्ताओं पर पडेगा। अधिकांश कार्य यहां पर पूरे भारत में ठेकों पर सौंपकर, ठेकों के बिलों पर वसूली का निश्चित हिस्सा कार्यालयों से लेकर दिल्ली स्थित मुख्यालय मंत्रालय तक यथा योग्य बंट रहा है।

इसी क्रम में अब इंटरनेट ब्रॉडबैंड के कनेक्शनों और उसके चालू करने, आकर शुरु करके दिखा जाने, और जाते ही बंद हो जाने का ठेका भी किसी सिंघवी ग्वालियर की फर्म को दे दिया गया हैं। उधर दूसरी इंटरनेट सेक्शन में बैठे वहां का भ्रष्ट शूकरों का स्टॉफ जान बूझकर ब्रॉडबैंड कनेक्शनधारी को परेशान करने की नियत से जानबूझकर स्पीड न केवल कम ज्यादा करता है बल्कि इस ठेकेदार फर्म से कमीशन डकारने के आधार पर स्वयं परेशान कर उपभोक्ताओं के काल अटेन्ड करने के बहाने जानबूझकर बिल बढाने के लिए भेजता है। कभी स्पीड पूरी भी दिखाई देती है परंतु पेज और साइटे खुलती ही नहीं है। अगर ज्यादा कुछ कहों तो 2537777 पर शिकायत दर्ज करवा दीजिए फिर वहीं कहानी दोहराई जाएगी। आखिर ये भ्रष्ट, शूकरों, निकंमों की फौज अपना ही आशियाना उजाडने क्यों पर तुली है। सितम्बर 10 से अभी तक लेंडलाइन बिलों का ठेका भी टाटा कंसलटेंसी को दे दिया। कमीशन पर तो शूकर भी अंटशंट बिलिंग कर पूरे लैंड लाइन उपभोक्ताओं से अवैध वसूली कर रहा है। ताकि सारे लैंड लाइन ग्राहक खत्म हो जाए, पूरा निगम बंद हो जाए।

साप्ताहिक समय माया

38 प्र.श. वाणिज्य कर 34 कस्टम एंड एक्साइज 6 प्र.श. उपकर

अर्थात 78 प्रतिशत, डीजल पेट्रोल पर

कर के बाद भी सभी बड़ी, लंबी सडकों पर टोल टैक्स

पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो लगभग 70000 किमी से ज्यादा है। केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो वास्तविकता में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग लूट प्राधिकरण बन चुका है। 90प्रतिशत सडकों पर जो 63000 किमी है इसमने रु.2 से 3 करोड प्रति किमी की सडकों को रु.10 से 16-17 करोड तक में प्रत्यक्ष में गिरवी और परोक्ष में बेंच दिया है। इन बीओटी सडकों में अधिकांश ठेकेदार फर्मों के मूल में राजनैतिक सांसदों केन्द्र के मंत्रियों से लेकर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पोश डकैतों का ही पैसा लगा है। इन सडकों की मंजूरी में, ओर प्राधिकरण के मंडल में केन्द्र के 5 सचिवों, वित्त, वन एवं पर्यावरण, भूतल परिवहन निर्माण और रखरखाव, विधि और खर्च के होते है जो इन प्रोजेक्ट को मंजूरी देते है। बेचारे ये डकैत मात्र रु.1 करोड़ ही लेते है। अर्थात प्रोजेक्ट की कीमत में रु. 5 करोड़ में तो ये जुड जाते है। रु. 10-20 लाख से रु. अधिकतम रु.4 करोड प्रति किमी, सडक पर पोता मारने से लेकर, पुरी नई सडक बनाने की कीमत रु. 4 करोड तक उसमें 40 किमी से ज्यादा बडा नया पुल न बनाना हो, बाकी सारा कमीशन मंत्री से लेकर मंत्रालय में बैठे सचिव, मुख्य अभियंता, अधीक्षण, कार्यपालन, सहायक, सुपर वाइजर से लेकर चपरासी तक सबका यथा योग्य रु.2 से 3 करोड प्रति किमी स्वाभविक है। जो ठेकेदार के लूट की पूरी छूट के साथ मिलता है। फिर वह चाहे सोनवाय का टोल पिगडंबर बनाए इंदौर उच्च न्यायालय कुछ भी फैसला दे, ओरिएंटल तो पिगडंबर में टोल बनाएगी। यहां के भ्रष्ट प्रबंधक श्रवण कुमार सिंग कुछ भी भ्रमित करने वाली जानकारी दे। चाहे उनके अकीटोल वाली सडक पर गाडी का पहिया न भी छूए। तो भी डकैतों को लूट और वसूली की पूरी छूट दी जाएगी। स्वाभाविक है, आंदोलन आग पकडेगा। जबकि 38 प्रतिशत राज्य वाणिज्यकर, 34 प्रतिशत का कस्टम एक्साइज, 2 प्रतिशत शिक्षा उपकर, 2 प्रतिशत सडक उपकर, 2 प्रतिशत अन्य उपकर जनता पेट्रोल और डीजल की कीमत पर वाहन चालक चुकाता है। पर लोकतंत्र लूटतंत्र बनकर जनता पर लूटने को तुला हुआ है। जिन विदेशों से ये तरीका बीओटी का लेकर आए थे केन्द्र और राज्यों के भूतल व लोक निर्माण के अभियंता व अन्य सलाहकारों की फौज उसने सभी लोकतांत्रिक देशों में एक समान्तर सड़क शासकीय खर्चों से निर्मित व संधारित की जाने वाली, जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से मुफ्त में चला जाता है। जिसकों सुविधाजनक सडक चाहिए उसे बीओटी सडक पर टोल देकर गुजरना होगा। ये शूकरों की फौज लोकतांत्रिक सडक का मूल वहीं छोड आई।

मप्र में भी मप्र सड़क लूट निगम ने भी यही किया इन हरामखोरों ने तो बनी बनाई सिंगल लेन सडकों को भी ठेकेदारों के हवाले कर दिया उन्होंने मोटरेवल सडके लेकर एक पोता मारकर 5 से 10 लाख खर्च करके ही लूटना शुरु कर दिया। उज्जैन-झालवाड, रायसेन-राहतगढ, खंडवा-होशंगाबाद जैसी अनेकों सडकें सिंगल लेन होने के बाद भी 3 से 5 वर्ष गुजरने के बाद भी साधारण और पुर्ननवीनीकरण के नाम कुछ भी नहीं हो रहा। पर 15 से 30 वर्ष तक की लूट अवश्य जारी है। अर्थात अगले 15 से 25 वर्ष तक सडकें लूट के ठेकेदार के पास होने से न तो ढंग से संधारित होंगी। और न ही उनके 2 लेन और 4 लेन पर काम होगा। मंत्रियों, सचिवों, इस लूट निगम का प्रबंध संचालक श्वानों की भांति अपनी लूट का टुकडा दबाकर उसी में बैठकर आराम फरमा रहे है। मप्र के राजमार्गों से जुडे वाहन चालक और जनता को आंदोलन के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता।

पूरे प्रदेश में भूमाफियाओं के इशारे पर पूरे शासकीय कार्यालय नृत्य करते है। उनके लिए जिले के कलेक्टर से लेकर संभागायुक्त, ग्राम एवं नगर निवेश, नगर-पालिकाए, निगम, नगर पंचायतों से लेकर ग्राम पंचायतों तक, पंजीयक, मुद्रांक व क्रय विक्रय भूसंपत्तियों, गांव के पटवारी से लेकर राजस्व निरीक्षक तक व अन्य सभी शासकीय कार्यालय यथा सहकारिता, पंजीयक फर्मस व समीतियां, कंपनी रजिस्टार आदि तक नोटों का बंडल हजम करने वाले श्वानों की फौज से ज्यादा कुछ नहीं। ये भूमाफिया और सरकारी कार्यालय मिलकर किसी भी जमीन पर कब्जों झूठी रजिस्ट्रीयां नामांतरण भू उपयोग परिवर्तन, मुख्त्यार नामों के जरिये खेल सकते हैं। एक ही जमीन, प्लाट मकानों को अनेकों को बेचकर पैसा डकारते हैं। ज्यादा प्रताडनाओं, जालसाजियों के विरूद्ध जनता कहीं न कहीं प्रदर्शन करती है। फिर दो नं. का कालाधन व्यापारियों, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों से लेकर मंत्रीयों, राजनीतिज्ञों सरकारी अधिकारियों आदि का इस खेल आग में घी का काम करते हैं। लडाई-झगडों, अपराधों, हत्याओं में 10% अपराध इसी से जुडे होते हैं। इसमें अरबों रु के खेल होते है। जिसमें ऊपर से होकर नीचे तक सबके हितों का साधन होता है। निराश्रितों, कमजोरों की गुंडे-बदमाश, भू-माफिया खुले में संपत्तियां हडप जाते है। इनमें बाहरी तो क्या खूनारिश्तों में भी ये सब कुछ चलता हैं। कब्जे, हत्याये, अपहरण ,जालसाजियां आदि इसमें पुलिस भी भूमिका अदा करती हैं। जिनकी चर्चायें हर दिन दैनिक पत्रों में होती हैं। यहां पर भी जनता का आक्रोश फूटता है धरने, प्रदर्शन, शिकायतें जिसमें छोटे न्यायलयों से लेकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश तक जुडे होते हैं। जैसे न्यायाधीश बालकृष्ण के मामलें में हो रहा है। जमीनों से जुडे मामलों में आये दिन प्रदर्शन होते ही रहते हैं।

रा.रा. 59 पर दुर्घटनाओं और मौत का रास

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग लूट प्राधिकरण ने म.प्र. में जो राष्ट्रीय राजमार्गों के बीओटी के अंतर्गत सड़क बनाने के ठेकों 4 से सांढ़े पांच गुना ज्यादा कीमतों पर हेतु केंद्र में बैठे अधिकारियों, मंत्रियों और सांसदों के रिश्तेदारों की कंपनियों को ठेके सौंपे हैं। हरामतोर, जालसाज ठेकेदार और इर लूट प्राधिकरण में बैठे भ्रष्ट और जालसाज अधिकारी अपनी कमाई के लिये कैसे नंगा नृत्य कर रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण इंदौर अहमदाबाद मार्ग क्रं 59 पर देखा जा सकता है जिसका ठेका में आई व्ही आरसीएल इंदौर गुजरात टोलवेज प्रा.लि. को 155 कि.मी. लंबाई जो इंदौर से 9.5 कि.मी. से 171 कि.मी. के लिये 1175 करोड़ में दिया गया था। इस मार्ग पर मार्च 2010 से कार्य शुरु कर दिया गया था, इस हरामखोर जालसाज फर्म के साथ इंदौर का परियोजना संचालक श्रवण कुमार सिंग भी महीना वसूली कर रहा है वो यह नहीं देख रहा है, कि सड़क बनाने के साथ ही म.प्र. लोक निर्माण विभाग के रा.रा. संभाग ने जैसी यातायात चलने योग्य जो सड़के सौंपी थी, उसको नई 2 लेन सड़क बनने तक उस का रख रखाव भी करना हैं। अर्थात अप्रैल 2011 से ठेका होने वाले इन हरामखोरों ने मात्र घाटा बिल्लौद में बरसात में होने वाले गड्ढों में भराई करवाई थी बाकी 9.5 कि.मी. से 171 कि.मी. तक उस पुरानी सड़क पर इस डकैत फर्म ने एक पैस खर्च नहीं किया। जबकि इन्हें सड़क बनाने के साथ पुरानी सड़क को भी तरीके से स्तर बनाये रखने हेतु यातायात की सुगमता के लिये उसके संधारण की पूरी जिम्मेदारी थी, इसके संबंध में इंदौर के इस लूट प्राधिकरण के पीडी श्रवण कुमार सिंग ने पूछा गया तो कार्य प्रगति पर की रट ही लगाये रहा, इस सड़क की दूर्दशा पर एक न्यायाधीश ने भी उच्च न्यायालयच इंदौर के याचिका लगाई थी, यहां पर पूरे मार्ग पर पुरानी सड़क पर मुश्किल से दूरी फुटी सड़क पर डामर और गिट्टी दिखती हैं। इस 155 कि.मी. पूरे मार्ग पर हर दिन 25-50 सड़क दुर्घटनायें हो रही हैं। जिसमें सबसे ज्यादा मोटरसायइकिल वाले हैं। लपेटे में आकर इस ऊबड़ खाबड़ सड़क पर हाथ पैर तुड़वाने के साथ एक दो मौतों का सिलसिला आम हो गया हैं। दुर्घटनाओं और मौत के इस रास लीला की मुश्किल से ही संबंधित थानों में रिपोर्ट लिखी जाती हैं। क्योंकि घायल पहले अपना इलाज करवाये या पुलिस की बत्तमीजी और जानलेवा कार्यवाहियों से ह्रबह्र हो जहां तक इस संबंध में विद्यान सभा म.प्र. में भी प्रश्न लगाकर एक विधायक ने जानकारी चाही थी, इसमें भी इस पीडीएम के सिंग ने और प्रदेश के कार्यालय में बैठे मुख्य महाप्रबंधक और क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. के आर के पांडेय ने जो हास्यापद जवाब दिये तो इन जालसाज धूर्त भ्रष्टों की मानसिकता और कार्यप्रणाली को स्पष्ट करते हैं।

दिल्ली के भूतल परिवहन मंत्रालय और भारारा लूट प्राधिकरण के मुख्यालय से लेकर नीचे परियोजना संचालक तक अंतिम इकाई तक सभी जगह धूतजालसाजों और भ्रष्टों की फौज तो बैठी हैं। दूसरी और जितनी भी ठेकेदार और सलाहकार फर्मे है वे सब भी सफेद पोश डकैतों का गिरोह हैं। जिन्हें केवल लूट से मतलब हैं। सड़कों पर जनता का वाहन चालकों के.... हो रही हैं। डकैतों को तो बस धन चाहिए, 72 मौते तो पुलिस के रिकार्ड में आ गई, जो दुर्घटनाग्रस्त होकर चुपचाप अपने गतव्य की और इलाज करवाने के दौरान मर गये ऐसे भी 200 से ज्यादा का उस मार्ग के खाते में ही हैं, दूसरी और सड़क की इस बदहाली पर जनता के धरने, प्रर्दशन जनहित याचिकायें तक लगाई पर इन शुअर डकैतों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बस हर जगह एक की राग .. कार्य चल रहा है उन्नति पर हैं।

अकेले इसी मार्ग पर 3.5 से 171 कि.मी. के 155 कि.मी. के दोनों और 10-10 मी. में अर्थात 15000X20=31,00000 वर्ग मी में लगभग पूर्ण विकसित 30 लाख से ज्यादा पेड़ों की कटाई इसी आईव्हीआरसीएल इंदौर गुजरात टोलवेज लि. द्वारा करके बैच कर हजम कर गई जिस कीमत ही औसतन रु 25000 प्रति पेड़ लगाई जाये तो रु 750 करोड़ लकड़ी का में फायदा मुफ्त में हजम कर गये। इस पर न तो म.प्र. के वन विभाग ने कुछ कहा न म.प्र. सरकार ने, न ही दिल्ली में बैठे धूर्तों के जमावड़े के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने और न ही भूतल परिवहन मंत्रालय ने जबकि दोनों और पूर्ण विकसित सागौन, बबूल व अन्य सैकड़ों प्रजातियों के 25 से 50वर्ष पूराने 40 से 50फीट ऊंचे तक पेड़ लगे थे। जबकि यह लकड़ी म.प्र. के वन विभाग के संबंधित जिले के कार्यालय में जमा करवाई जाना थी, बेशक इसके संबंध में स्पष्ट प्रावधान है कि जितने पेड़ काटे जायेंगे उसके 5 गुना पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, पर जो वर्तमान में या उस क्षेत्र के अधिग्रहण के समय लगे पेड़ों को पूरे म.प्र. में इस लूट प्राधिकरण जिसके पास वर्तमान में लगभग 3500 कि.मी. सड़के हैं 35 करोड़ से ज्यादा पेड़ कटाई करवा कर बिकवा डाला, परंतु न तो इन्होंने ठेकेदारों से लकड़ी को संबंधित जिलों के वन विभागों का सौंपने के लिये कहा और न पूछताछ की, आखिर सरकारी अधिकारी, खासतौर पर केन्द्रीय सरकार के ये भ्रष्ट हरामखोर कानून सरकारी, सार्वजनिक संपत्तियों को अपने बाप की जागीर क्यों समझते हैं। इंदौर खलघाट के मामलें में भी उच्च न्यायालय इंदौर ने भी उक्त मार्ग की ठेकेदार फर्म को सोनवाय में अपना टोलबूथ लगाने को कहा, इसके विपरीत बीओटी ठेकेदार इसे पिगडंबर में लगाने पर ही काम कर रहा है, दूसरी ओर परियोजना संचालक श्रवण कुमार से पूछा गया तो उसका कहना था कि मैंने तो कंपनी को पत्र भेज दिया है, मानना न मानने का ठेकेदार का कार्य है, सलाहकार फर्म और मा.रा.रा.प्रा. दोनों ही आंख मींच कर धन डकार कर ठेकेदार को मनमानी करने की छूट देकर एक तरफ अनावश्यक रूप से पीथमपुर या वहां से बाहर जाने वालों से जब वसूली करेगी तो हर दिन न केवल विवाद लड़ाई-झगड़े और मारापीटी तो होगी ही हर दिन पुलिस केस बनेंगे। साथ ही टोल चलने तक नित्य नये न्यायालयों में प्रकरण सौंपे जायेंगे, इसमें भी सीबीआई और सीबीसी को शीघ्र प्रकरण सौंपे जायेगे, परंतु ठेकेदार कंपनी पिंगडबर में टोल बूथ स्थपित कर लें, फिर प्रकरण ठोस बनेगा, तब ही पीडी एसके सिंग और ठेकेदार फर्म पर सीबीआई भी ठोस कार्यवाहीं कर सकेगा, इस प्रकार अगला टोल अनुबंध रद्द करवाने में भी जनता लाभ ले सकेंगी।

खाद्य नागरिक आपूर्ति ने ओपचारिकता निभाई

मजाक बन गया विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च

इंदौर। मप्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण के इंदौर कार्यालय ने गांधी हाल में 15 मार्च को उपभोक्ता सरंक्षण दिवस मनाया। जो पूर्णतः औपचारिकताओं की खानापूर्ति करने वाला कार्यक्रम बन कर रह गया यहां पर, इंदौर जैसे प्रदेश की व्यावसायिक और मालवा की राजधानी के रुप में जाना जाता है। जहां की जनता प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में ज्यादा जागरुक समझी जाती है। में आयोजित कार्यक्रम की प्रस्तुति इसलिए दी जा रही है ताकि मप्र के अन्य जिलों और पूरे देश की स्थिति को नमूने के रुप में जाना जा सके।

बेशक इंदौरी मिडिया, मप्र के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के शब्दों में झूठन चाटने वाले भांडों की फौज हे शब्दशः सत्य है भले ही कडवा है। अर्थात यहां के मिडिया के पत्रकारों को बस टुकडे डालों और जो चाहे छपवालो। वे केवल तारीफ छापना जानते है। कानून, औचित्य, जनहित, इनके लिए महत्वहीन है। इसलिए इसके पूर्णतः फ्लाप शो के बारे में न छाप सके।

जिला खाद्य नियंत्रक को 3 दिन पूर्व एसएमएस करके कहा गया था, कि बीमा कंपनियां फोन और सेल्युलर कंपनियों, आइल, पेट्रोल जैसी उपभोक्ता से जुडी सभी कंपनियों को बुलाया जाए, ताकि जनता अपनी समस्याओं के बारे में बता सके। उनकी समस्याओं के निराकरण के प्रयास किए जा सके।

इसके विपरीत इस आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण विभाग इंदौर शहर के नगर निगम उसके साफ सफाई, खाद्य एवं स्वास्थ्य विभाग व अन्य किसी भी विभाग का अता-पता ही नहीं था। विद्युत मंडल, फोन कंपनियों जिसमें बीएसएनए, एयरटेल, रिलायंस, टाटा व जो लैंडलाइन मोबाइल फोन सेवाएं देती है का भी पता नहीं था। वोडाफोन और आइडिया मात्र दो सेल्यूलर कंपनियां थी। बीमा स्वास्थ्य, डाकघर भी नहीं थे। सांची दूध, पचोरी गैस एजेंसी और उसके लठैतों की फौज, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नापतौल पेट्रोल पंप एसोसिएशन का काउंटर था।

गैस वालों की तरफ पचौरी गैस एजेंसी का काउंटर था जहां गैस एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ कंपनी के भी आदमियों के साथ कुछ हट्टे कट्टे लठैत भी बैठे थे, स्वाभविक था श्री अजमेरा जी ने कैमरे के साथ पूछताछ शुरु कर दी, कितने दिन की बुकिंग चल रही है, उत्तर मिला 7 दिन की, कहा गया कि 15 दिन से महीने भर में भी गैस नहीं पहुंच रही है। जवाब दिया गया कि कंपनी से माल नहीं आ रहा है। तो बाजार में 700 रुपए में घरेलु गैस कैसे ब्लेक में उपलब्ध हो रही है। हमें नहीं मालूम, तो फिर किसे मालूम है। अब लठैतों के साथ कंपनी के प्रतिनिधि, पचोरी गैस के प्रतिनिधि के चेहरे तमतमाने लगे। चलिए छोडिये नए कनेक्शन कितने में देते है। रु.4400 में क्यों, गैस चूल्हा जो रु.2200 में देते है। बाजार में रु. 700-800 का मिल जाता है। तो रु.1400 ज्यादा क्यों, फिर चूल्हा क्यों दिया जा रहा है। कनेक्षन तो मात्र रु.2150 का है तो रु.2150 में ही दिया जाना चाहिए। कोई जबरदस्ती नहीं है। पर कंपनी के काउंटर पर तो जबरदस्ती ही की जाती है। अब लठैत खडे हो चुके थे। कंपनी का प्रतिनिधि भी गुर्राने लगा था। इतने में एक खाद्य निरीक्षक पहुंचे और श्री अजमेरा को खींचकर ले गए। बाद में मालूम पडा कि उन्होंने कुछ जनता के आदमियों को मारा-पीटी भी की, तो ये थी व्यवस्था। इसलिए न तो जिलाधीश महोदय, निगमायुक्त, संभागायुक्त न अन्य विभागों जिसमें स्वास्थ्य, विद्युत मंडल आदि के कोई जिम्मेदार अधिकारी थे। क्योंकि वहा पर पहले से ही मारा-पीटी की व्यवस्था थी गैस वालों की तरफ से।

सांची दूध के नमूने पिछले 15 वर्षों से क्यों नहीं लिए गए। तो जवाब था कि हम क्या करें नहीं लिए गए तो। तो कहा गया कि जब कोई खाद्य निरीक्षक आपके नमूने लेने की कोशिश करता है। तो आप

गैस वितरकों की गुंडा फौज ने जनता को भी पीटा, कलेक्टर, निगमायुक्त कोई नहीं आया

कलेक्टर से फोन करके धमकवाते है। क्योंकि आपके सांची गोल्ड में भी 6 से 8 प्रतिशत फेट की जगह 2 से 4 प्रतिशत ही फेट भी नहीं होता है। आपकी रु. 5 और 11, 12 भी थैलियों में पूर्णतः पाउडर से दूध बनाकर पैकिंग की जाती है। क्योंकि आपके पास जितना दूध आता है। उससे डेढ गुना कहां से और कैसे बेचते है। नहीं ऐसा नहीं है। तो श्री अजमेरा ने कहा चलिए आप बता दीजिए कैसा है? तो वह प्रतिनिधि कहने लगा कि आप फैक्ट्री आइए।

इस उपभोक्ता दिवस का पूरा दम 2 से 2.30 बजे तक पूरी तरह से निकल चुका था। यहां तक कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के भी न तो निरीक्षक थे, न ही कोई अधिकारी।

भारत में भी जनता को उतरना होगा सडकों पर

भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी से भविष्य खतरे में

सारे कानून बहुराष्ट्रीय कं. के हित में, रोटी महंगी कारें सस्ती

पूरी दुनिया में क्रांति की बयार बह रही है। भारत में भी बाबा रामदेव ने आवाज उठाई तो भ्रष्ट धूर्त दिग्गी दानव ने कहा स्वयं रामदेव की कमाई की जांच की जाए। बेशक उनकी कमाई दवाओं, किताबों, योग शिक्षा से की है। धूर्त नेताओं, मंत्रियों और अधिकारयों की तरह जनता के धन में से वेतन लेने के बाद भी विकास के नाम पर बाबा रामदेव ने डाका नहीं डाला।

नेता, मंत्री, अधिकारी तो पूंजीतियों की रखैल बन, सरकारी संपत्तियों को कमीशन खोरी के चलते उनके हाथों गिरवी रख रहे है। जैसे रिलायंस के पास कहां से आए, तेल और गैस के अपार भंडार जो कि ओएनजसी ने खोदे थे।

सारा नमक आयोडिन नमक के नाम टाटा केमिकल्स को दे दिया गया पूरे देश की आबादी के मात्र 0.02 प्रतिशत लोगों को ही आयोडिन नमक की आवश्यकता थी। 50 पैसे. किलों का नमक 12 रु. किलो बैचकर 40 वर्षों से जनता को लूट रहे ।

पूरे देश के राज्यों के विद्युत मंडलों को भंग कर क्यों खरबों रु. संपत्तियां, पावर प्लांटस, टाटा, रिलायंस आदि का कमीशन के चलते बेंचे जा रहे है। परमाणु समझौता मात्र कमीशन खोरी के लिए ही किया गया। युरोपीय देश परमाणु बिज़लीघरों के निकलने वाले रेडियों एक्टिव कचरे से परेशान है। उनके समय बाधित परमाणु प्लांटों को मात्र कमीशन के लिए आयात कर देश के पर्यावरण और धरती को बिजली के नाम क्यों घातक परमाणु विकिरणों का हजारों वर्ष नष्ट न होने वाले घातक प्रभावों में झोंका जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 क्या रिलायंस और इंडियन बहुराष्ट्रीय कंपनी को के लाभ के लिए नहीं बनाया गया इससे लगभग 5 करोड बेरोजगार और 30 करोड दाने-दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। कारों से कर हटाए जा रहे है। और रोटी छीनी व महंगी की जा रही है।

देश की जनता को दो वक्त की मिले न मिले। पर बहुराष्ट्रीय कं. को अच्छा सस्ता माल खरीद कर विदेशों को निर्यात कर 100-500 प्रतिशत तक लाभ कमाए। कृषिमंत्री, गेहूं,दाल-चावल, शकर, चना, मक्का से लेकर सूखे मेवे, खाद्य तेल, फलों तक का निर्यात करने की छूट देकर 5 से 10 प्रतिशत तक कमीशन उकार जाए। जब देश में त्राहि-त्राहि मचे तो आयातकों को सडा-गला, स्तर हीन गेहूं, दाल, चावल, शकर, तेल तक आयात करने की खुली छूट देकर उस आयात में 10-25 प्रतिशत तक कमीशन डकार जाए। जब जनता चिल्लाए तो वह सडता हुआ शूकर मंच से खडा होकर चिल्लाए शकर, दाल, चावल, तेल खाना छोड दो। गरीब ज्यादा खाने लगे है। नहीं खाओंगे तो मर नहीं जाओंगे। कहकर जनता का अपमान करे, स्वाभाविक है जनता के पास सडकों पर उतरने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं बचेगा। ताकि सरकार वायदा व्यापार बंद करे। आयात निर्यात बंद करें, बैंकों द्वारा खाद्य वस्तुओं पर ऋण देना

बंद किया जाए ताकि भंडारण न किया जा सके जनता के धन को बैंकों द्वारा बडी बहुराष्ट्रीय कं. व्यापारियों को ऋण देकर, उसी जनता को लूटने की पूरी व्यवस्था भी रिजर्व बैंक के इशारे पर बैंकों द्वारा ही की जाती है। बैंके ही जमाखोरी करने में, स्टॉक पर ऋण और साख सीमा बढाकर कर्ज देकर अहं भूमिका निभाते है। परिणामस्वरुप कभी तेल गायब, कभी गेहूं, दाल, चावल गायब बदले में पर्याप्त उत्पादन और स्टॉक होने के बाद भी त्राहि-त्राहि मची रहती है।

वायदा व्यापार ने सोने-चांदी से लेकर खाद्य तेलों, कपास, गेहूं, दाल, चावल आदि तक की कीमतों को आसमान दिखा दिया है। इनके भावों के उतार-चढाव की सीधी काली-सफेद कमाई ने जमीनों की कीमतों को दिन दुगना और रात चौगुना बढाया अब आम आदमी के लिए न केवल मप्र के इंदौर, भोपाल से लेकर गांवों तक में कीमतों में हर वर्ष भारी उछाल आया है। उसके लिए छत का सपना दूभर हो गया। इसके विपरीत दो नं. की काली कमाई का पैसा जमीन जायदाद में आंख मींचकर धडल्ले से लगाया जा रहा है। अर्थात आक्रोश जनता के मन में धीरे-धीरे पनप रहा है।

राष्ट्र की आजादी के समय, पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों की ही अच्छाइयों और बुराइयों को ध्यान में रखकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया गया था। पूंजीवादी घोर शोषण के विरुद्ध ही जिनका साम्यवाद 20 वीं शताब्दी के प्रारंभ में चलन में आया। पर साम्यवाद की दीर्घ कालीन धारणा को भी कमजोरी और मक्कारी ने धराशाही कर दिया। इन सबके गुण दोषों के आधार पर ही भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया गया था पर नरसिंहा राव की सरकार ने धूर्त अमेरिका और यूरोपियन देशों के विश्व व्यापार संगठन की कठ पुतली बन पूरे राष्ट्र के शासकीय उपक्रमों का पूंजीकरण कर विनिवेश की नीति अपना कर राष्ट्र के विद्युत मंडलों, बैंकिंग, बीमा, गैस, तेल, उत्पादन, पैट्रोलियम व अन्य राष्ट्रीय और राजकीय उपक्रमों में विनिवेश की नीति को अपना कर बहुराष्ट्रीय, विदेशी कंपनियों के हाथों में सौंपना शुरु कर दिया। पूंजीवाद की तरफ बढते इन कदमों ने पुनः आम नागरिकों का शोषण शुरु कर दिया।

मप्र में ही मप्र विद्युत मंडल के कंपनीकरण के बाद और उसके षडयंत्रों जिसमें हर काम ठेके पर करवाने के परिणामस्वरुप पिछले 15 वर्षों से हर वर्ष दो से तीन बार बिजली की कीमतें बढाने के बाद भी बिजली की आपूर्ति किसानों, जनता और उद्योगों को पूरी नहीं मिल पा रही है। दूसरी और उसमें बैठाए गए सारे हरामखोर आईएएस जिन्हें बिजली की एबीसीडी भी नहीं आती हर वर्ष रु. 300-500 करोड डकार बिजली कंपनियों को 1200 से 2000 करोड का घाटा भी दिखा रहे है। जनता का किसानों का और उद्योगपतियों का न केवल आक्रोश बढ रहा है। वरन कई विद्युत मंडल के कार्यालयों में आगजनी की घटनाए भी आम हो गई है।

यही हाल गैस एजेंसियों का है। यहां पर भी केन्द्र सरकार कहती है, 24 घंटे में उपभोक्ता को गैस मिल जाएगी। इसके विपरीत गैस एजेंसियां 15 से 30 दिन उस सिलेंडर नहीं पहुंचाती है। और ग्राहक कोई कुछ कहता है या बहस करता है। तो गैस एजेंसियों के पाले गुंडे ग्राहकों से मारपीट करने लगते है। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस पर जिसे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति संयोजित करता है। इंदौर की पचोरी गैस एजेंसी ने उस दिन गांधीहाल में गुंडे बुलवाकर रखे थे। इस हरामखोर के उन गुंडों ने गांधीहाल में ही जनता के साथ मारपीट की और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के अधिकारी व निरीक्षक उसे देखते रहे। प्रदेश और देशभर में अधिकांश गैस एजेंसियों के गैस सिलेंडर को रु.390/- का सिलेंडर रु.700 तक में बेंचने की शिकायतें मिलती है। परंतु न केवल पैट्रोलियम कं. उनके क्षेत्रीय विपणन प्रबंधक तक सब इस लूट खसोंट में शामिल होते है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के भ्रष्ट निरीक्षकों से लेकर जिला खाद्य अधिकारी तक महीना वसूली कर शांति-शांति का राग अलापते है। बदले में जनता फिर तोड-फोड करती है। फिर पुलिस केस बनाकर जनता को प्रताडित किया जाता है। कब तक चलेगा।

मप्र जल संसाधन विभाग

इंदौर संभागीय कार्यालय बंद करने की तैयारी

शहरी विकास, ग्रा.यां.से., पंचायतें, कृषि लो.स्वा.यां. उद्यानिकी क्यों करते है। जल संधारण, जबकि 70 प्रतिशत धन बर्बादी में जाता है। विशेषज्ञ बेगारी करते है।

इंदौर का पलासिया स्थित मप्र जल संसाधन विभाग का संभागीय कार्यालय को बंद करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। शीघ्र ही प्र.स.रा.श. जुलानिया आदेश जारी करेंगे और यह कार्यालय सदा के लिए यहां से बंद कर उज्जैन संभाग के कार्यालय में मिला दिया जाएगा। अध्ययन करने पर जो कारण सामने आए उसमें इंदौर जिले की सारी कृषि, नजूल, वन विभाग आदि की अत्यधिक कीमतें और व्यावसायिक उपयोग के चलते यहां नए जलस्त्रोतों का निर्माण व अधिग्रहित जमीनों उनका मुआवजा तो महंगा हो ही गया है। साथ शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किसानों को जमीन अधिग्रहण का मुआवजा देने के बाद भी अधिकांश किसान अधिक मुआवजे के लिए न्यायालयों की शरण में चले जाते है। जल संसाधन के अधिकारियों का कहना है, कि एक शासन किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में करोडों रु. खर्चकर जल उपलब्ध करवाए, किसान 1 के स्थान पर 2-3 फसलें भी लें, मुआवजा भी लें और हमें न्यायालय में भी सैकडों प्रकरणों इंदौर, जबलपुर और दिल्ली तक भी दौडएं इससे बेहतर है कि ये संभाग ही बंद हो जाए ताकि न तालाब, बांध और नहरें बनाएंगे न परेशानी उठाएंगे। किसानों में हो दम तो स्वयं के दम पर सब कुछ करें। नहीं तो जमीनें बेंचकर उद्योगों में मजदूरी करें अर्थात कम से कम भविष्य में शासन तो इंदौर जिले में कोई तालाब बांध और नहरें नहीं बनाएंगा, नेताओं की भी मर्जी यही है। जमीनों की खरीद फरोख्त से मोटा धन वसूला जाए, सागभाजी, दलहन, तिलहन, अनाज के लिए आजू-बाजू बहुत से जिले है। क्या जरुरत है, इंदौर जिले में खेती करने की।

जल संसाधन विभाग का कार्य है वर्षा के जल संचयन हेतु स्त्रोतों तथा तालाब बांध नहरों आदि का निर्माण और रखरखाव करना। जब इसके लिए पूरा विशेषज्ञों का एक विभाग है। तो क्यों वह शहरीय आबादी के लिए पेयजल व अन्य उपयोग के लिए तालाबों, बांधों और नहरों आदि के कार्यों को संपन्न नहीं करता । नगर निगम इंदौर, बिलावली यशवंत सागर पर हर वर्ष करोडों रु. खर्च करके भी किस ठिकाने पर पहुंचा। फिर जल स्त्रोतों की स्थापना के लिए कृषि विभाग खेत का पानी खेत में, बलराम तालाब योजना पर करोडों खर्च करता है। मनरेगा, ग्रामीण यांत्रिकीय विभाग, उद्यानिकी विभाग, ग्राम पंचायतें लोक स.वा.यां. आदि हर वर्ष अरबों रु. बर्बाद करती है। जलस्त्रोत बनाने और रख रखाव में। आखिर क्यों? जब पूरा एक विभाग जिसके पास विशेषज्ञ इंजीनियर्स सहायक इंजीनियर्स सुपरवाइजर्स आदि सब है। तो क्यों लोक स्वा. यांत्रिकीय, ग्रामीण यांत्रिकीय, पंचायतों, कृषि विभाग को क्यों यह पैसा बर्बाद करने के लिए दिया जाकर, न तो उसका ठीक से रखरखाव किया जाता है। न ढंग से निर्माण होता है दूसरी तरफ उसके विशेषज्ञों के पास काम न होने से उन्हें मुफ्त का वेतन देते-देते शासन ही स्वयं उस विभाग को इंदौर जैसे 30 लाख की आबादी वाले प्रदेश के बडे जिले से जिला स्तर का कार्यालय ही बंद करके अन्यत्र स्थानांतारित कर देना चाहता है।

इस औद्योगिक जिले में उद्योगों के लिए बरसाती पानी को एकत्रित कर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्त्रोत नहीं है उन्हें नर्मदा जल की आपूर्ति पर करोडों रु. का ऋण लेकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण के अंतर्गत लाइनें बिछा कर पेय जल की आपूर्ति की जा रही है। बेशक उसमें नेताओं, निगमायुक्त, लोकस्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के डकैत भी वसूली में शामिल है। पेयजल की लागत की तोहमत जब देखो जनता पर लगा दी जाती है। जबकि उद्योगों के विकास के समय उन्हें 65 किमी दूर से पानी लाकर, साफकर, तैयार किया गया पेयजल आपूर्ति की शर्त तो कहीं नहीं थी। अभी असरावद में मेक्डावेल ने अपनी फ्रेंचाई देकर जल पेकिंग कर बाटलों में भरकर बेचनें का प्लांट डाला है। जल स्त्रोत क्या है। कहने को ट्यूबवेल है जबकि इस जालसाज ने भी नर्मदा की लाइन का ही सदुपयोग कर करोडों रु. कमाएगा। भुगतान के नाम संबंधित अधिकारी को रु. 5000 महीना देकर निगम को चोट पहुंचाई जाएगी। तृतीय चरण के 90 एमएलडी पानी में मात्र 30 एमएल डी पानी ही पेयजल में उपयोग किया जाकर जनता तक पहुंच रहा है। बाकी निगम अधिकारियों के माध्यम से सांवेर रोड, लक्ष्मीबाई नगर, पोलोग्राउंड व शहर के 400 नर्सिंग होम्स, अस्पतालों, 165 पानी पाउच पैकर्स, नमकीन, मिठाइयों से लेकर दारु पैक करने वालों तक कालोनियों तक पहुंचाया जा रहा है। जिनसे 10 प्रतिशत आय भी नहीं होती निगम को।

आखिर इनके लिए जल संसाधन विभाग से कहकर जल की आपूर्ति के लिए स्त्रोत क्यों नहीं बन वाए जाते। यशवंत सागर बांध में मात्र रु. 5-8 करोड खर्च हुए पर कागजों पर रु.30 करोड, आखिर इतने पैसे को इस विभाग के माध्यम से बांध विशेषज्ञों से क्यों नहीं बनवाया गया। और क्या सब कुछ और हमेशा के लिए हो गया। भविष्य में भी और वर्तमान में इंदौर के चारों तरफ उद्योगों की आपूर्ति के लिए इस विभाग बंद करने की अपेक्षा उसे काम क्यों नहीं दिया जाता और सस्ते जल की आपूर्ति क्यों नहीं करवाई जाती। नेताओं जनप्रतिनिधियों को चाहिए की जलसंसाधन के इस जिला कार्यालय को बंद करने की अपेक्षा उसका बेहतर सदुपयोग करे, क्योंकि इंदौर की आबादी के साथ काम धंधे भी बढेगे। जल स्त्रोतों की आवश्यकता भी बढेगी। दीर्घगामी जल स्त्रोतों के लिएविभाग की आवश्यकता सदा ही बनी रहेगी।

बहुत भारी पड़ेगी चीन घुसपैठ की अनदेखी

पृष्ठ 8 का शेष

उसने सबसे पहली अपनी क्षमताओं का आंकलन कर लिया, दूसरा उसका पारंपारिक शत्रु जापान को नष्ट करके उसे 5 वर्ष पीछें धकेला, तीसरी और जापान में विकसित हुए इलेक्ट्रानिक जिसमें घड़ियों से लेकर मोबाइल, कैमरे, कम्प्यूटर्स, खिलौने आदि सैकड़ों वस्तुओं जो आम आदमी की जरूरते बन चुकी है। चीन नकल करके सामानांतर सामग्री बना कर दुनिया में बैच रहा था पर जापानी गुणवत्ता के कारण उसे दुनिया के हर देश में बदनामी झेलना पड़ती थी। उसने उस जापान को ही बर्बाद कर दिया। अब चीन का पूरी दूनिया में कोई प्रतियोगी नहीं रह गया। इसलिए वह अब पूर्णतः स्तरहीन बिना गारंटी, पूर्णतः असुरक्षित भाल पूरी दुनिया में बेंचकर अपनी अर्थव्यवस्था को ठोस कर रहा है, दूसरी तरफ उसकी अर्थव्यवस्था की यह मजबूती भारत के लिए सैन्य, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से घातक होती जा रही है। यदि वो भारत पर आक्रमण कर देता है सीधे तोर पर भी तो भी भार में कृषि उत्पादन के अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन इतना जबरदस्त नहीं कि वो चीन की बराबरी कर सकें, और युद्ध की स्थिति में अर्थ व्यवस्थाओं को संभाल सकें। दूसरी और जेसा विस्फोट जापान के निकट समुद्र में कर जापान को तबाही का मंजर दिखा दिया वैसा ही मंजर वो अप्रत्यक्ष युद्ध में भारत को भी दिखा सकता है। हमारी समुद्री सीमा गुजरात में कच्छ की खाड़ी से लेकर कलकत्ता और हुवली तक फैली हुई है, यदि उसने मुंबई, कांडला, चेन्नई, कोलकत्ता आदि के पास समुद्र में जापान की तरह का प्रयास किया तब हम क्या करेंगे।

वर्तमान में भारत का ऐसा कौन-सा मित्र है जो चीन के आक्रमण के समय भारत को सहयोग करेगा, जिस अमेरिका की गुलामी हमारा प्रधानमंत्री करता है। युद्ध में वह सहयोग नहीं वसूली करेगा। क्योंकि पाकिस्तान रूपी सांप को वो अपनी गोदी में बैठाकर आर्थिक सामारिक आंतकीयों को धन का दूध पिलाता है। फिर पाक की नियत कश्मीर को उड़ाने और अलग करने की है, इसलिये वो चीन की मन से सेवाए दे अपनी तन रूपी धरती उपलब्ध कराता रहा है, अर्थात हम चारों तरफ से घिरे हैं। और हमारे सत्ताधीश मन से राष्ट्र रुपी तन को नोचने में लगे हुए हैं।

तो उन का ध्यान सीमाओं पर कैसा जाएगा, इसलिए वो जातिवाद का जहर फैलाकर राष्ट्र का जातीय संघर्ष में उलझाकर अपने भ्रष्टाचार के कुकर्मों से ध्यान बांटाने में लगे हुए हैं। कांग्रेसी डकैत जनता को अपनी सैन्य शक्ति के बारे में भुलावे में रखे हैं। चीन की सैन्य शक्ति से हम एक तिहाई है। फिर दूसरी और सेना में वर्तमान आंकलन के हिसाब से 25000 अधिकारी और 20 लाख सैनिकों की आवश्यकता है। कच्च गुजरात से लेकर राजस्थान पंजाब, कश्मीर और लेह तक 1500 कि.मी. लंबी सीमा पाकिस्तान से सटी है। और लेह से 2000 कि.मी. लंबी चीन से अर्थात 3500 कि.मी. लंबी सीमा की चौकसी के लिए कम से कम 19500 चौकियां धरती पर 15000 बंकर जमीन के अंदर चाहिये, वास्तविक व्यवस्था है। इससे पाठक अनमिज्ञ नहीं है। क्योंकि युद्ध के समय चीन और पाकिस्तान मिलकर पूरे क्षेत्र में हमला करेंगे। फिर कच्छ से लेकर कोलकत्ता तक लगभग 7000 कि.मी. की लंबी समुद्री सीमा में जल सेना भी हमारी सेना खासी मजबूत तो दूर मुंबई के हमले इसकी गवाहीं दे रहे हैं। बंगला देश से दोस्ती की उम्मीद भी बेईमानी है। कैसी सुरक्षा है जनता अंदाज लगा सकती हैं। जबकि 30 अप्रैल को अरूणांचल के मुख्यमंत्री खांडू का चापर उड़ान के 20 मिनिट भी गायब हो गया आम बुद्धिजीवि का मत है, उसे पूर्व में दुर्घटना ग्रस्त हुए चापर की तरह चीनी मिसाइलों ने गिराया गया है। और केन्द्र की नपुंसक कमीशनखोर सरकार इस सच को जानबूझकर छीपा रही है, क्योंकि चीन से सीधी लड़ाई लड़ने की औकात नहीं भारतीय सेना में, इसलिए मीडिया में मंत्री नेताओं के बोलने पर रोक लगा दी गई है। ये हैं, केन्द्र सरकार का निकंमापन और डरपोकपन और चीन की युद्ध की ललकार।

साप्ताहिक समय माया

बदला और रु. 25 हजार प्रति दै.वे.भो. नहीं मिले

मु.मं., मंत्री व भ्रष्ट पीएस स्वाई, प्र.अ डामोर को लूट की पूरी छूट

पेयजल के नाम भ्रष्टों की लूट का तांडव, नियमों की धज्जियां

भोपाल। लो स्वा.पां. विभाग में पदस्थ भोपाल के मुख्य अभियंता विजयवर्गीय के निलंबन के पीछें दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के आधार बनाकर जो खेल खेला गया वास्तविकता में उसके पीछें कई महत्वपूर्ण कारण सामने आये हैं। जिसमें एक तो दैनिक वेतन भोगीयों को नियमितीकरण से पहले रु. 25000 प्रति कर्मचारी की मांग का पूरा न होना जिसमें रु 10 हजार प्रतिकर्म चारी महाभ्रष्ट आपराधिक प्रवृत्ति के प्रमुख अभियंता का कार्यभार संभाल रहे जी एस डामोर को रु.15 हजार प्रति कर्मचारी प्र.स. आर के स्वाई, मंत्री व अन्य को देने के आरोप सामने आ रहे हैं। दूसरी और अधिकांश पीएचई के अधिकारियों जिसमें प्रधान सचिव सचिव, प्रमुख अभियंता मुख्य अभियंताओं अधीक्षण यंत्रीयों के यहां जो 10 से 25 दैनिक वेतनभोगी घरों पर बंगलों में काम कर रहें हैं। वो हरामखोरों की फौज इस मुफ्त की सुविधा को हाथ से जाने देना नहीं चाहते इसलिए उच्च और सर्वोच्च न्यायालयों के आदेशों की भी न केवल धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

वरन स्वयं भाजपाई चुनाव घोषणा पत्र में किये गये वादे को भाजपा सरकार होने के बाद भी दैनिक वेतन भेगियों को नियमित करने के मामलें में कोई भी सरकारी अधिकारी सहानुभूति पूर्वक सोचना ही नहीं चाहता जब कि हर विभाग में हर प्रदेश भर 30 वर्ष से ज्यादा समय समय से वो न्यूनतम मजदूरी पर बाबुओं की भांति कार्य कर रहे हैं। और वेतन दैनिक मजदूरी का दिया जा रहा हैं। यदि पद नहीं है, तो 30 वर्ष से पूरे प्रदेश में हजारों कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को ये महाजालसाज, अपराधी, भ्रष्ट प्रमुख अभियंता के रूप में कार्य कर रहा है। डामोर प्रधान सचिव आर के स्वाई मंत्री बिसेन और प्रमुख सचिव अवनि वैश्य बताये कि क्या इन सब को इनकी दैनिक मजदूरी का वेतन घर बैठ कर पहुंचाया जा रहा हैं। क्या यदि हां इस मुफ्त खोरी में अपना कितना हिस्सा हैं। दूसरी और सच यह भी है कि मुख्य अभियंता से विजयवर्गीय से इन दैनिक वेतन भोगियों के बहाने अपने भ्रष्टाचारों के मामलें उजागर करने के बदले की कार्यवाही से ये हरामखोरों, जालसाज दहशत फैला रहा हैं। ताकि कोई भी इस अपराधी के भ्रष्टाचारों के विरूद्ध भविष्य में न बोल सके। मुख्य अभियंता विजयवर्गीय इंदौर के म.प्र. सरकार के वाणिज्य आईटी आदि के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के रिश्तें में समधी लगते हैं। इस धूर्त हत्यारे कार्यवाहक प्र.अ. डामोर का इतिहास रहा हैं, कि ये अपने कुकर्मों को दबाने के लिऐ इसने सामान्य वर्ग के कई अधिकारियों का न केवल निलंबन वरन् नौकरी से भी बाहर करवाया हैं। जिसमें ईई पलवल का नाम सबसे ऊपर हैं।

ये अपने हर पाप में दो चार सामान्य वर्ग के अधिकारियों को लपेट कर चलता है, ताकि मामला खुल जाने पर उन पर जांच बैठाने निलंबन करवाने नौकरी लेने के खेल में तो सब निपट जाये और ये बच निकले। अभी जब से कार्यवाहक प्रमुख अभियंता बना हैं, चारों तरफ ऐसे निकंमों और भ्रष्टों की फौज बैठा रखी ताकि उनसे ये धन के आवंटन में 15 से 25प्रतिशत डकार सकें। इस प्रकार 31 मार्च 11 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में रु. 500 करोड़ तक का चंदन घिस दिया दिया लोक स्वा.यां को। इसने अब इंदौर संभाग में का.अ. अहिरवार जिसकी बीबी ड्राइवर के साथ भाग गयी थी जिसकी खबरे दैनिक समाचार पत्रों में बिना इसका नाम लिखे चारों तरफ खूब बिना अर्नेस्ट मनी के टेंडर धड़ल्ले खुल जाते हैं, पिछलें फरवरी 10 से ये भ्रष्टाचार अहिरवार लगातार कर रहा हैं। ये भ्रष्टों की फौज ध्यान देने को तैयार नहीं है।

यहीं कारण है कि ये भ्रष्ट सूचना आयोग के आदेश फरवरी 11 से अभी तक कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। यहीं हाल इंदौर वृत्त के संभागों का है जहां तक अधीक्षण यंत्री सोलंकी का है ये भी अपने विधायक भाई के सहयोग से पदासीन होकर के वेतन पत्रक पर हस्ताक्षर करने के ही शौकीन हैं। स्टॉफ ने जो कि भूसाखेड़ी का महाधूर्त, निकंमा और मठ्ठा है जैसा लिखकर दे दिया बस हस्ताक्षर कर दिये जाते है। यहां वर्षों से पदस्थ नागर अंधीक्षक की सेवा करते रहिये, बस सबकुछ शांति-करते रहें तो जहां तक मुख्य अभियंता का सवाल हैं। पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुसार प्र.अ. की कठपुतली है उसकी बला से बया हुआ था, नहीं से कोई मतलब नहीं जो डामोर कहेगा वंदा उस पर हस्ताक्षर कर देगा, विभाग के ही पदस्थ अधिकारियों के अनुसार सब जगह लूटों खाओं मचा हुआ हैं। पूरा विभाग भगवान भरोसे चल रहा है। इसी विभाग का यांत्रिकीय अंचल जो पूरे म.प्र. की नलकूप खनन व अन्य यांत्रिकीय व्यवस्थाए देखता है यहां भी चारों तरफ बंदर बांट मची हुई हैं। उज्जैन संभाग को यांत्रिकीय संभाग में बैठा का अ.ने अपनी गाड़ियों को अपने रिश्तेदारों के नाम से विभाग में रु.18 से 20,000 प्रति माह पर अटेच कर रखी हैं।

जबकि पूरे प्रदेश में अधिकांश 1-2 वर्ष पुरानी गाड़िया भी और नई गाड़ियों रु. 12000 से 14000के बीच किराये पर ली गई हैं। जबकि बिना टेंडर बुलाये इसने अपनी रिश्तेदारों मित्रों की गाड़ियां भी 4 से 5 वर्ष पुरानी भी रु 18 से 20000 में अटेच कर रखी है। इस संभाग में लगी मशीनों के रख रखाव और डीजल में ही रु. 1 से 2 करोड़ का खरीदी जिसमें नलकूपों के पाइप आदि में रु.2 से 3 करोड़ के अतिरिक्त इसे 2 फरवरी 10 से दिनांक 25.10.10 तक भी लगभग रु.11 करोड़ 20 लाख का आवंटन मिला, जिसमें 3.2.10 को पत्र क्र. 166 में हायड्रो एवं नलकूप सफाई में रु. 39 लाख 10.3.10 को पत्र क्र. 194 से रु. 1.50 करोड़ का उज्जैन संभाग के शासकीय विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था पत्र क्र. 216 से शालाओं में नलकूप खनन के लिए रु. 1 करोड़ 18.04.10 शालाओं में पेयजल के लिए रु. 50 लाख फिर 02.07.10 को पत्र क्र 74 से रु. 2 करोड़ 11 लाख 25.10.10 को पत्र क्र. 172 से रु. 1 करोड़ 10 लाख 50 हजार इस प्रकार रु. 11 करोड़ 20 लाख को पत्र क्र. 74 से 2 करोड़ 11 लाख 25.10.10 को पत्र क्र. 172 से 1 करोड़ 90 लाख 50 हजार इस प्रकार रु. 11 करोड़. 20 लाख में से भी इस बंदे ने रु. 3 करोड़ से ज्यादा डकारे, अर्थात बांटने के बाद भी में यह राशि रु. 16 करोड़ 74 लाख जबलपुर में रु. 17 करोड़ 50 सागर में रु. 15.26 करोड़, ग्वालियर में रु.7 करोड़ 24 लाख रीवा में रु. 11 करोड़ 97 लाख में से लगभग रु. 6 करोड़ विशुद्ध रुप से क.अ. ने डकारे ही होंगे। यह पूरा संभाग भारी डकैतों का हैं। जहां बस कागजी आंकड़ों की ही होती हैं। इंदौर संभाग में यह आबंटन रु. 11 करोड़ 8 लाख 90 हजार था। इंदौर रख रखाव संभाग रेडियों कॉलोनी पानी की टंकी में भी रु. 22 से 25 करोड़ के आवंटन में से अहिरवार ने अधिकतर स्तरहीन कार्य भी रु. 5 से 7 करोड़ का ही करवाया। पूरे प्रदेश में यहीं लूट मार चारों तरफ चल रही है भाजपा के भ्रष्टों की अंधेर नगरी चौपाट राजा चल रहा हैं।

इंदौर नगर निगम में भी तीसरे चरण का पानी आने के बाद भी जानबुझकर मात्र 6 माह में पाइप लाइनें फूटने लगी। बेशक कमाई का जरिया हैं। तृतीय चरण का पानी आने के बाद भी टैंकर चलेंगे। भिया पार्षदों और उनको पट्ठों की दारू का खर्चा हाथ खर्चा रु 50 हजार महीना आना आना बंद हो गया। इसलिये टैंकर तो चलाना ही पड़ेगें, फिर टैंकरों से ड्राइवर क्लीनर से लेकर कमिश्नर और महापौर तक सब ही त्रस्त रहते हैं। फिर पहले, दूसरे, तीसरे चरण से फैक्ट्रीयां फार्म हाऊस और खेत भी तो सीचें जाना हैं। कॉलोनियों में भी पानी में करोड़ो रुपए का इसलिए पानी का बटवाना आवश्यक हैं। फिर इतनी सारी कालोनियां नो पिछलें दस वर्षों में बनी उनसे भी तो घन डकारा हैं। उन्हें 6-6 के कनेक्शन दे दिए हैं। बाई पास रिंगरोड़ टंकी कॉलोनियों जिनमें इन धूर्त पार्षद, नेताओं, अधिकारियों की भी हिस्सदारी हैं। आखिर पानी उन्हें भी देना पड़ेगा, दिल बड़ा होना चाहिए, बिल तो मध्यम वर्गीय देना हैं। गरीबों को पानी पिलाना पड़ेगा और अमीर पाइप फोड़कर पी जाएगा, उनसे कैसा और काहे का बिल।

आखिर पीडीपीएल के सारे नमूने पास हो ही गये

रु. 5 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत पर मामला साफ

उप नियंत्रक राम कृष्ण, त्रिवेदी ने धन हजम कर नमूने बदल खेल किया

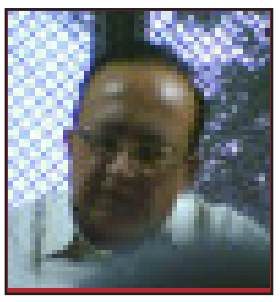

इंदौर। दूषित आईवी फ्लूड्स से उम्मेद चिकित्सालय में जोधपुर में हुई 16 महिलाओं की मौतों का जो तूफान राष्ट्रीय स्तर पर उठा था, जिसमें पीडीपीएल द्वारा प्रदाय की गई है। फ्लुडस का उपयोग किया गया था। म.प्र. के खाद्य एवं औषधी नियंत्रक विभाग के 5 महाभ्रष्ट जादूगरों औषधि निरीक्षक आशीष त्रिवेदी, गर्ग, वरिष्ठ निरीक्षक शोभित कोष्ठा अजय ठाकुर, अशोक गोयल आदि ने इसके नमूने लिये थे, जो पूर्णतः इन हरामखोरों द्वारा की गई कार्यवाहीं की औपचारिकता मात्र था।

यहां पेरेन्ट्रल ड्रग्स एंड फार्मा. लि.के. पांच संचालक विनोद गुप्ता, मनोहरलाल गुप्ता, मुरलीधर गर्ग, अनिल मित्तल जो प्रारंभ से ही महाजालसाज रहे हैं। प्रेम फार्मा भी कई संचालक हैं। जो सारा उत्पादन निम्न स्तरीय करते हैं। चूंकि औषधि विभाग इन की कठपुतली है, इसलिये उन्हें किसी की भी चिंता नहीं रहती हैं। इन चारों जालसाज हरामखोर संचालकों ने अपने निम्न स्तरीय उत्पादनों से नुकसान, मरीजों की तबियत बिगड़ने, मौत होने पर कानूनी कार्यवाहीं, गिरफ्तारी और सजा आदि से बचने के लिये इसे सारे कारोबार का मुखिया संजय शाह को प्रबंधक के रूप में नौकरी पर रखा हुआ है। यहां भी जालसाजी की गई हैं। इसके अंतर्गत इन्होंने एक कं. पेरेन्ट्रल सर्जिकल लि.बना रखी हैं। जो पीडीपीएल की मार्केटिंग के है। उससे ये कागजों पर सर्जिकल युनिट्स के ठेके और आदेश पर माल बना कर आपूर्ति करते हैं। ताकि इनकी औषधियों से कोई भी दुर्घटना घटने पर अपनी जिम्मेदारियों कानूनी कार्यवाहियों से बचने के लिए सार्जिकल कहें, मैं तो विपणन व्यवस्था देखता हुँ मुझे तो माल की आपूर्ति पीडीपीएल ने की थी, और पीडीपीएल कहें हमने तो पेरेन्ट्रल सार्जिकल के कहने पर माल बनाया था, और कानूनी तौर पर मामला उलझ जाये और ये धूर्त जालसाज बच जाये। दूसरी और लाभांश को भी कंपनियों में बाटकर दिखाये ताकि आयकर, विक्रय कर, कस्टम एंड एक्साइज की चोरी के साथ ही श्रमिक कानूनों, पीडीएफ औद्योगिक सुरक्षा आदि के भी कारनामों व अन्य कानूनी कार्यवाहींयों से बचे रहें, वर्तमान में भले ही इन चारों विनोद गुप्ता, मनोहर गुप्ता, मुरली गर्ग, अनिल मित्तल आदि ने उम्मेद चिकित्सालय जोधपुर में 17 गर्भवती महिलाओं की मौत के मामलें में रु.5 करोड़ से ज्यादा खर्च कर अपने आप को बचा लिया हैं। इस मामलें में अभी कई पेंच है। जिससे खद्य एवं नियंत्रक मनोहर अगनानी जो अभी चुनावी ड्यूटी पर गये हुए हैं। मामला फिर खोला गया तो भी चारों धूर्त बच निकलेंगे और प्रबंधक के रूप में नियुक्त संजय शाह को ही सजा भुगतना पड़ेगी।

हर कंपनी को अपने सभी इंजेक्टवल के हर बैच की 40 शीशीयां सेंपल के रूप में उत्पादन के दिनांक से औषधि की निश्चित समय बाधित तिथि के बाद 3 साल 3 महीने तक सारे सेंपल नियंत्रित औषाधि नमूना कक्ष में रखाना चाहिए जो पूर्णतः वातानुकूलित होना चाहिए और उसे दोहरे नियंत्रण में जिसमें लगने वाले दोहरी चाबी एक उत्पादक के पास और दूसरी शासकीय औषधि नियंत्रक के कार्यालय में संबंधित और औषधि निरीक्षक के पास रख जानी चाहिए ताकि कभी भी जब भी ताला खोलना हो तो दोनों चांबियो को लगाने के बाद ही ताला खोलकर इसे नियंत्रित नमूनों को कभी भी प्रयोगशाला में भेजकर उसकी जांच करवाई जा सके। इस पीडीपीएल में इजेक्टेवल के ऐसे नमूने रखने की कोई जगह ही नहीं है। न ही केवल आईवी फ्लुड्स की प्रतिदिन 50000 बाटल पैकिंग करता है उसकी 40 बोतलें जबकि उसके पास ऐसे इजेंक्टवल के 15 से ज्यादा उत्पाद हैं। अर्थात 15-40-365 दिन 5 वर्ष 2 वर्ष की एक्सपायरीडेट से 36 माह ही मानें। तो भी 10,95000 बोतलें रखने में कोई वातानुकूलित करने की व्यवस्था ही इस फैक्ट्री में नहीं हैं। तो ये कौन से नमूने ले लिए गये 25 और 26 फरवरी 11 औ.नि. अजय ठाकुर, अजय गोयल ने जो तत्काल अच्छे बैच के बनाये गये थे, दूसरा ऐसी किसी भी कार्यवाही में 2 स्वतंत्र जनता के जाने माने व्यक्तियों के सामने नमूने लेने और गवाहों के हस्ताक्षर करवाने का प्रावधान भारतीय दंड प्रक्रियां संहिता में है इन नमूनों के समय भी लागू होता हैं। परंतु पांचों हरामखोर औषधि निरीक्षकों व औनि शोमिल को आशीश त्रिवेदी, गर्ग, ठाकुर और गोयल ने नमूने भर कर अपने और फैक्ट्री मालिक के हस्ताक्षरों से ही नमूने भेज दिये पुनः बेच रिकॉल करवाकर, जो तत्काल के भरे गये थे, जिनमें पुराना बैच नं डालकर भरे गये बिना किसी स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर के इसलिए ये नमूने लेने की प्रक्रिया ही पूर्णतः अवैध थी। जब जो बैच का माल जोधपुर भेजा गया था, उस बैच के कंट्रोल सेंपल रखने की फैक्ट्री में जगह ही नहीं थी, दूसरा उस कंट्रोल सेंपल के कक्ष की चाबी औषधि निरिक्षक के पास ही नहीं होती तो बाकी सारी कार्यवाहीं तो व्यर्थ अपने आप ही सिद्ध हो जाती हैं। कोई भी फैक्ट्री मालिक कंपनी का माल खरीदकर इन बिके हुए हरामखोरों औषधिनिरीक्षक के सामने अपनी शीशी और अपनी फैक्ट्री के रेपर में पैक करके मन चाहा बैच नं. डालकर नमूने देते हैं। जो प्रयोगशाला में आंख मींचकर पास भी हो जायेंगे ये फिर वहीं निम्न स्तरीय अपना माल पैक करके पूरे देश में ही क्यों दुनिया में बेंच रहें हैं। पाठकों को शायद ज्ञात नहीं होगा कि इन्हीं औषधि निरीक्षकों के निरीक्षणें और एप्रसेल रिर्पोट पर फैक्ट्री को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्यता भी मिली हुई है। अर्थात इसका माल देश में ही नहीं वरन् विदेशों में भी निर्यात के लिये अधिकृत हैं। इस फैक्ट्री के मालिकों को बचाने के लिये न केवल म.प्र. औषधि नियंत्रक कार्यालय में बैठे उपनियंत्रक दिनेश श्रीवास्तव से लेकर स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय औषधि उप नियंत्रक रामकृष्ण से लेकर इंदौर के वरिष्ठ उपनियंत्रक औषाधि त्रिवेदी जो इन्हे बचाने के षड़यंत्र का सूत्रधार है। सबने लाखों लेन-देन कर इस पीडीपीएल को बचाया गया बेशक वरिष्ठ औषधि निरीक्षक शोमिल कोष्टा ने अभी तक उत्पादन पर से प्रतिबंध हटाने के लिये मना कर दिया था। पाठको को यह जानकार हैरानी होगी कि इंदौर में इंजेक्टेबल औषधि उत्पादन ईकाइयों के वर्षों से नमूने नहीं लिये गये हैं। एक रीनी फार्मा के इंजेक्टबल में एक नमूने में कांच के अंश पाये गये थे। उसके विरूद्ध भी औनि त्रिवेदी ने अभी तक प्रभावी कार्यवाहीं नहीं की हैं। म.प्र. के खाद्य एवं औषधि नियंत्रक मनोहर अगनानी चूंकि अभी चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में म.प्र. से बाहर हैं। इसलिये उन्हें सारी वास्तविकतायें, पूर्णतः ज्ञात नहीं आईएएस लॉबी में डॉ.मनोहर अगनानी की ईमानदारी के चर्चे चलते रहते हैं। उनके आने के बाद इस नाटक का क्या अंत होता हैं यह अभी शेष हैं। हाल ही में इंदौर के एमवाय में भी आईव्ही फ्लूड्स की बोतलों में फंगस पाई गई। विभाग की ओर से वृंदनानी नमूने लेने गए। 17000 बोतलें दूषित पाई जाने के बाद भी सारी बोतलें वहीं छोड़कर आ गए ताकि पीडीपीएल सारा माल ले देकर बादल सके। वृंदनानी ने भी रुपए 5 लाख लेकर छोड़ दिया।

मप्र वाणिज्य कर-95 प्रतिशत स्टाफ से कागजों पर आंकडों की खेती

क्या पूरी टेक्स वसूली में सक्षम है एंटी इवेजन

तो बाकी स्टॉफ को स्थानांतरण करो, क्यों बर्बाद कर रहे वेतन..?

इंदौर। मप्र वाणिज्य कर के मुख्यालय से लेकर जिला स्तर पर बैठे अधिकांश अधिकारी कर्मचारी सारे दिन सूचनाएं एकत्रित कर जानकारी भेजने में लगे रहते है। स्वाभाविक है। व्यापारी जनता से तो वाणिज्यकर की वसूली नियमानुसार कर लेता है। परंतु 99 प्रतिशत व्यापारी झूठे, टेक्स रिटर्न भरकर मात्र 10-20 कर ही चुकाता है। चूंकि नियमित अधिकारी, निरीक्षक, कर्मचारी को कोई अधिकार नहीं होते उनकी जांच के इसलिए वो जानकर भी कुछ नहीं कर सकते जब हर अधिकारी निरीक्षक और कर्मचारी वाणिज्य कर की वसूली, शासन के नियमानुसार करने के लिए बैठा है। परंतु यह काम वर्तमान में केवल एंटी इवेजन ब्यूरो की अ और ब विंग के साथ मप्र की अन्य एंटी इवेजन ब्यूरो की टीम करती है। जो मात्र 1 प्रतिशत से ज्यादा चोरी न तो पकड पाती है। न उनके पास इतने साधन, न स्टाफ है जो कर चोरी को 10 प्रतिशत भी रोक सके। हॉ इतना अवश्य है। एंटी इवेजन ब्यूरो वाले ट्रॉसपोर्ट रो, बस आप्रेटरों से जो अवैध माल ढोते है। महीना जरुर वसूली कर रहे है। जिनसे महीना वसूली होती है। तो सब ठीक है। जो नए ट्रक आप्रेटर्स यहां लपेटे में आ जाते है। उनकी रसीदें काट दी जाती है। इसे अ और ब विंग के संबंधितों के सैंकडों प्रकरण बिना स्क्रूटनी के इनके पास लंबित पडे रहते हे। कइयों का निपटारा वर्षों से लंबित है।

दूसरी ओर महाभ्रष्ट सहा. आयुक्त आर पी श्रीवास्तव जो पिछले 15 वर्ष से इंदौर में पदस्थ होकर चारों तरफ भ्रष्टाचार का तांडव कर रहा है। कम्प्यूटर खरीदी में 500 से 800 प्रतिशत पर कम्प्यूटर खरीदी की गई जिसकी लोकायुक्त को शिकायत की जा रही है। ऐसे अनेकों अधिकारी और कर्मचारी यहां वर्षों से पदस्थ है। भ्रष्ट जैसे सीटीओ सुलेखा जैन, व अन्य कई, जिन्हें शासन पाल रहा है। वर्षों से इंदौर में जमे है। इनको इस चुनावी मौसम में फील्ड में भेजा जाना चाहिए वैसे ये अपने आप को प्र.स. एपी श्रीवास्तव के परिवार का कह कर स्थानांतरण नहीं होने देता अर्थात प्र.स.एपी श्रीवास्तव भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो ऐसे भ्रष्टों को संरक्षण दे रहे है। लोकायुक्त की रिपोर्ट में इनका भी नाम शामिल कर दिया जाएगा।

जहां तक एंटी इवेजन ब्यूरो के इंदौर अ और ब विंग के साथ ग्वालियर, भोपाल, जबलपुरा, छिंदवाडा व अन्य सभी विंग की कारगुजारियों पर पुरा वाणिज्य कर विभाग के चपरासियों से लेकर अधिकारियों तक सब अंगुलियां उठाते है। और पूछते है। कि आखिर विभाग में इतनी सारी कारें और वाहन है तो निजी टेक्सीयां क्यों चलवाई जा रही है। एक और विभाग के ही किसी खास को खास लाभ दिलवाने के लिए। दूसरी ओर इन टेक्सियों के ड्राइवर ही बडी ट्रांसपोर्ट लॉबी के निरंतर संपर्क में रहकर ट्रांसपोर्ट वालों को खबरें देने की न केवल एक तरफ तो स्वयं महीना वसूली कर रहे है। तो दूसरी ओर वो ट्रकों को छुडवाने में दलाल की भूमिका का निर्वहन भी करते है। फिर जो ट्रक घेर कर इंदौर में ही अफीम गोदाम में खडे किए जाते है। वहां निजी सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी में काम चलता है। वो स्वयं ही ठेकेदार बन गए है। और वाले-वाले ही ट्रकों से पैसा वसूलकर चलता कर देते है। आखिर अफीम गोदाम में सुरक्षा की दृष्टि से विभागीय कर्मचारी-अधिकारी पदस्थ क्यों नहीं किए जाते जो ट्रकों की आवाजाही के बारे में जिम्मेदार ठहराए जा सके।

अक्टू.-नव. 10 में आयुक्त ने ट्रकों को पकडने जांच करने और वसूली के लिए पूरे प्रदेश के स्टॉफ को फील्ड में उतारा था तब एक महीने में ही कई गुना ज्यादा टेक्स वसूली हुई थी। उससे चारों तरफ कर चोर व्यापारियों में हडकंप मच गया था और उन्हें बदनाम करने के लिए वसूली के आरोप लगा दिए गए थे, तो व्यापारी वसूली कब देगा। जब वह चोरी करेगा। ईमानदार से तो कोई वसूली नहीं कर सकता। बेशक इससे एंटी इवेजन ब्यूरो पर आरोप लगे कि हम महीना भी दें। और गाडियों भी पकडी जाए, ये वसूली की हवा बनाने वाले व्यापारी द्वारा हंगामा किए जाने के बारे में भी एंटी इवेजन ब्यूरो के ही लोगों की भूमिका थी। ताकि बदनाम कर पूरे स्टॉफ को वापिस उनक कमरों में बैठा दिया जाए। और ये छोटे-मोटे 5-10 ट्रकों को पकडकर अपनी स्थापना का औचित्य सिद्ध कर सके।

किसी को मतलब नहीं- आम आदमी की भूख और आंसू से

प्रथम पृष्ठ का शेष

इन 130 वस्तुओं में घरेलू बर्तनों से लेकर दो पहिया वाहन तक सभी आम ग्रामीण उपभोक्ताओं से लेकर स्कूली पाठ्य पेन, पेंसिल, दंत मंजन आदि तक सभी शामिल है। अर्थात इसका सारा बोझ भी गरीबों को ही उठाना है। अर्थात जो गरीबों को सुविधाओं दी गई थी उससे कई गुना ज्यादा उनसे वसूली कर ली जायेगी।

सेन्ट्रल एक्साइज से रु.164 हजार करोड रु. कस्टम से 151 हजार करोड और रु.82 हजार करोड रु. एकत्र किये जायेंगे जबकि इससे दुगुनी इसकी चोरी से अप्रत्यक्ष देने वाले करेंगे, जिसका सीधा भार आम जनता तो पूरा देगी परंतु रु. 500 हजार करोड रु की चोरी उद्योग पति, पूंजीपति, सेवा प्रदाता कर ही डालेंगे।

संयुक्त उद्यमिता या कार्पोरेट सेक्टर से चूंकि सीधा मोटा कमीशन वित्त मंत्रालय जिसमें प्रत्यक्ष जैसे आय कर आदि और अप्रत्यक्ष करों में कस्टम एक्साइज, सेवा कर केन्द्रीय विक्रय कर आदि आते हैं। सीधे ही प्रदाताओं से सरकारी अमला 30 प्रतिशत रिश्वत पर 70 प्रतिशत डकराने और चोरी करने की धूट दे देगा, यहीं कारण है कि कंपनियों पर अधिभार घटाकर 75 प्रतिशत से घटाकर 57 प्रतिशत कर दिया गया और विदेशी सहायक कंपनियों से मिलने लाभांश पर भी कर की घूट देकर पूंजीपतियों को ही लाभ पहुंचाया गया, कांग्रेसी डकैत मंत्रियों से आम आदमी को राहत की उम्मीद हो बेमानी हैं। वैसे भी कांग्रसियों को दृष्टिकोण से आम आदमी की औकात केवल इसके पूर्व और पश्चात कांग्रेसी सरकार उसे केवल दो वक्त की रोटी मुश्किल से राशन की दुकान पर खडा कर देने का इतिहास रखती हैं। वास्तविकता में लोकतंत्र से सरकार भले ही जनता द्वारा चुनी जाती है, पर चुने जाने के बाद हुये नेता पूंजीपतियों की गोदी में बैठकर जनता को नाचने का उनके इशारे पर खेल करता रहती है।

पहले ही केन्द्र सरकार पेट्रोल और डीजल कीमतों को बेतगाम तरीके से बढा कर आम आदमी को हर कदम महंगाई बढाकर गरीबों के मुंह से रोटी छीनने पर तुली है। जबकि देश की जरूरतों को पूरा करने के लिये पूरे देश में 50 से ज्यादा स्थानों पर गैस और तेल निकाला जा रहा हैं। आखिर ये राष्ट्र की गिद्धों का गिरोह कांग्रेस उसके बारे में बात नहीं करती हर वक्त उसे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से बढाती रहती हैं। दूसरी और पूंजीपतियों, बहुराष्ट्रीय और उद्योगपतियों के इशारे पर नाचकर उनकी सुविधाओं और लाभ के संविधान संशोधन से लेकर बजट संशोधन और निर्माण तक सब करती हैं।

फूड पार्कों का निर्माण और विस्तार, भंडराण और प्रशीतीकरण के विकास से जमाखोरों और पूंजीपतियों को ही लाभ मिलेगा, और संग्रहरण, जमाखेरी बढने से जो महंगाई बढेगी वह भी आम आदमी को दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलने देगी, पहले से ही इन गिद्ध कांग्रेसियों ने आईटीसी, रिलायंस तालमार्ट को फयदा पहुंचाने के लिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि 2006 बना दिया जिससे 4 से 5 करोड लोग बेरोजगार हो जायेंगे उनमें ये इन कंपनियों के विशाल फुड पार्क भंडारण और स्टोरेज से आसानी से लाखें टन माल जमा करेंगी और मनचाहे दामों पर बेंचेगी जो निकट भविष्य में स्पष्ट हो जायेंगा, अर्थात गरीबों ओर अमीरों के बीच खाई बढेगी, गरीब एक वक्त की रोटी के लिये भी मोहताज हो जाएगा।

कांग्रेस ने अपने ऐतिहासिक चरित्र की हो व्रत्ति की है इस बजट को पेशकर यदि 5राज्यों में चुनाव नहीं होते तो इस बजट के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों तत्काल बढा दी जाती साथ ही वर्ष 11-12 के बजट से बढने वाली महंगाई अपना असर मार्च में दिखाना शुरु कर देती।

म.प्र. सरकार के बजट में भले ही किसानों और कर्मचारियों को लाभ देने की बात कहीं गई हो पर भु.मं. शिवराज और वित्तमंत्री राघव जी ने कर्मचारियों को छठे वेतनमान और उसके अंतर की राशि के भुगतान के संबंध में पलटी मार दी, दूसरी तरफ किसानों सुविधाओं के नाम पर पाला पीडितों को रु. 700 करोड में से मात्र मुश्किल से हाथ में रु 350 व एसडीएम व दलालों ने रु. 300 से 350 करोड डकार लिया।

कृषि संबंध क्षेत्रों के विकास के लिये रु. 5057 करोड का प्रावधान किया गया है जो गत वर्ष से 32 प्रतिशत अधिक होने के वितपरीत किसानों को इसके रु 1000 से 1500 करोड का भी सीधा लाभ कहीं नहीं मिलने वाला अर्थात यहां प्रधान सचिव से लेकर ग्रामीण स्तर तक बैठे कृषि विस्तार अधिकारी रु .3 से 4 हजार करोड झूठे व्हाउचरों ही पुनर्रावृत्ति होगी।

ऊर्जा क्षेत्र के लिये रु. 5169 करोड गत वर्ष से 66 प्रतिशत अधिक, पूरे प्रदेश में म.प्र. विद्युत मंडल के विखंडन के बाद सारी व्यवस्थायें जब कंपनियों के द्वारा संचालित की जा रही हैं। हजारों गांव आबादी के 64 वर्ष बाद भी अंधेरे में गुजर बसर कर रहे हैं। गांवों को विद्युतीकृत करने की योजना नहीं है। सारे सारणी के ताप विद्युत ग्रहों को बंदर करने के लिये पिछलें 10 वर्षों से षडयंत्र किये जा रहे हैं। ताकि महंगी बिजली खरीदने में मोटा कमीशन हर मिनिट में मिलता रहें, अप्रशिक्षित स्टॉफ की नई भर्ती ठेकेदारों के माध्यम से की जा रही है, पुराने स्टॉफ को पदोन्नतियां नहीं दी जा रही है। तरीके से वेतन समय पर नहीं मिल पा रहा है। साल में दो बार से ज्यादा तक बिजली की कीमतों पिछलें 15 वर्ष से लगातार बढाई जा रही हैं। अपने हिस्से की एनएचडीसी एनटीपीसी की सस्ती बिजली बाहर बेंचकर महंगी बिजली टाटा, पावर, जिंदल, रिलांयस एनर्जी आदि से खरीदने में आंख मींचकर मोटा कमीशन डकार कर बिना टेंडर के अरबों रु. के भुगतान किये जा रहे हैं। दूसरी तरफ कंपनियों के एमडीएके रुप में बैठाये गये तकनीकी इंडियान एब्यूसिंग सर्विस के अधिकारी हर वर्ष रु 3 से 5 अरब डकार कर कंपनियों में जानबूझकर घाटा दिख रहें है। किसानों को फसलों के मौसम में भी सिंचाई के लिये 2 से 4 घंटे मुश्किल से बिजली मिल रही हैं। बिजली कंपनियां अनाप-शनाप बिलिंग करके किसानों का बिल न दे पाने की स्थिति में जेल पहुंचा रही है, तो किसानों को सस्तीदरों पर बिजली का अनुदान जो पिछलें वर्षों में दिया गया तो कहा गया जो पुनः रु. 1455 करोड का अनुदान का प्रावधान या राघवजी ने केवल उकारने के लिये किया हैं। ताकि इस ऊर्जा के धन के बंदर बांट की जा सकें।

सडकों के लिये रु. 3051 करोड- ग्रामीण सडकों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना में पिछलें 10 वर्षों से किया जा रहा हैं। इसमें 40000 कि.मी. ग्रामीण सडकों को राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से जोडा गया है, प्रदेश के अधिकांश राजमार्गों पर बीओटी के अंतर्गत 3 से 10 गुना ऊंचे दरों पर सौंपकर बीओटी ठेकेदारों से 10 से 20 प्रतिशत मासिक वसूली से अत सचिव, प्रधान सचिव, मंत्री मुख्य मंत्री और मुख्य सचिव उकार ही रहे हैं। 1000 से कम की आबादी के गांवों के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना पिछले वर्ष से चल ही रही है जिसमें इस वर्ष रु.2811 करोड का प्रावधान भी क्या विशुद्ध डकारने के लिए ही बनाया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रदेश के अधिकांश राजमार्गों के ठेकेदार कांग्रेसी व उनके सहयोगी सांसदों उनके रिश्तेदारों को राजमार्गों पर डकैती डालने के लिए सौंप ही दिए है। जैसे कि देवास-राऊ पर गायत्री कंस्ट्रक्शन जो कि दक्षिण भारत के सांसद रेड्डी के रिश्तेदारों की है जिसे सडक निर्माण से पूर्व ही लूट की खुली छूट दे दी जो अगले 30-40 वर्षों तक चलेगी।

0 आदिवासियों के लिए उपयोजन बजट में रु.4878.64 करोड का प्रावधान किया गया है। आदिवासियों का कितना भला प्रदेश के आदिवासी कल्याण विभाग के बाबुओं से लेकर धूर्त अय्याश, आपराधिक प्रवृत्ति का मंत्री विजय शाह होने दे रहा है। जगजाहिर है यहां भी कागजी खाना पूर्ति कर रु. 4000 करोड तक उकारा जाएगा। वास्तविकता में रु. 878-64 करोड हो आदिवासी विद्यार्थियों व अन्यों पर खर्च होगा।

0 अनुसूचित जाति उपयोजना रु. 3354.45 करोड में से रु.2000 करोड मंत्री, सचिव, प्रधान सचिव से लेकर विभागीय अधिकारी उकार जाएंगे। रु.1354.45 करोड अनुसूचित जातियों के सरपंचों से लेकर अन्य हितग्राही इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे उसमें भी विद्यार्थियों को ही ज्यादा लाभ मिलेगा।

0 सिंचाई के लिए 3603 करोड वर्तमान प्रधान सचिव रा.श. जुलालिया ने अधिकांश मालवा की सिंचाई योजनाएं बंद कर दी है। बुंदेल खंड में केन्द्र के बुंदेलखंड विकास योजनाओं का पैसा है। इसका अधिकांश पैसा10 वृद्ध और चार मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में ही चला जाएगा। यदी वह विभाग था जहां से इंडियन एब्यूसिंग सर्विस अधिकारी अरविन्द जोशी पकडा गया था।

0 पेयजल आपूर्ति की योजनाओं के लिए रु. 614 करोड, पेयजल संधारण के लिए रु. 430 करोड, यह राज्यांश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग का है। कुल रु. 1044 करोड इतना ही लगभग केन्द्रांश अर्थात रु.2100 करोड रुपए इस विभाग को मिलेगा। इस विभाग में चारों तरफ भ्रष्ट इंजिनियरों की भरमार है। जो सारा खेल कागजों पर ही नियम विरुद्ध संपन्न होंगे। वर्तमान में कार्यभारित प्रमुख अभियंता जीएस डामोर है। जिसके भ्रष्टाचार के किस्से लोकायुक्त से लेकर उच्च न्यायालय तक में विचाराधीन है। इसमें भी यांत्रिकीय खंड में भी अधिकांश मशीने सुधारने के नाम पर ही करोडों की बंदरबांट चल रही है।

0 लाडली लक्ष्मी योजना में रु.439 करोड की व्यवस्था की गई है। इसमें महिला बाल विकास के अधिकारी और कर्मचारी ही बंदरबांट में लगे है। लाडली लक्ष्मियों को दी जाने वाली राशि के आबंटन के बारे में दैनिक समाचार पत्रों में आए दिन प्रदेश के समाचार पत्र खुलासा करते ही रहतेक है। हितग्राहियों को चक्कर लगवाकर और मोटा कमीशन उकारने पर ही यह लाभ दिया जाता है।

0 नगरीय निकायों के लिए रु.2707 करोड इसमें से रु. 900-1000 करोड भ्रष्टाचार में जाएगा।

0 पंचायतों रु. 1680 करोड का प्रावधान प्रदेश की लगभग 30000से ज्यादा पंचायतों जिसमें 55393 गांव आते है, के विकास वेतन भत्तों के लिए है। इसका भी अधिकांश रु.1000 करोड तक की राशि सरपंचों से लेकर पंचायत आयुक्त, मंत्री तक येन-केन प्रकरेण सरपंचों, पंचायत सचिवों तक उकारेंगे। जिसका हिसाब कागजों पर भींठग से नहीं मिलेगा।

इस विभाग में बैठे सचिव उमाकांत उमराव से लेकर आयुक्त ही रालाल त्रिवेदी, पंचायत एवं समाज कल्याण में बैठे उपसंचालक स्तर के जिला अधिकारियों से लेकर पंचायतों के सचिवों तक हरामखोरी लूट और भ्रष्टाचार का तांडव होता है। 60 से 70 प्रतिशत तक पैसे इन शूकरों द्वारा करती है। जिसके तत्कालीक उदाहरण है पंचायत एवं समाज कल्याण विभागों में बंटने वाली पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को देखा जा सकता है।

0 शिक्षा के लिए रु.10043 करोड

पूरे प्रदेश प्राथमिक शिक्षा से लेकर महाविद्यालयीन शिक्षा तक निजी क्षेत्र की दुकानदारी बन चुकी है। शासकीय शिक्षा भी कल्याण कारी कम स्कूली शिक्षकों से लेकर शिक्षा मंत्री, सचिव प्रधान सचिव, मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री कमाई का स्त्रोत है। इसमें केन्द्र सरकार का मानव संसाधन मंत्रालय भी पीछे नहीं है उसने भी शिक्षा सेंस के नाम पर 2 प्रतिशत की वसूली 1988 से कर रही है। और सच्चे अर्थों में शिक्षा लूट का साधन है सरकर के लिए 8० प्रतिशत शहरीय अर्द्ध शहरीय विद्यार्थियों के माता-पिता और संरक्षक निजी क्षेत्र के स्कूलों में भेजकर खर्च उठा रहे है। तो आखिर शासकीय शिक्षा पर रु.10043 करोड उकार लिया जाएगा। ग्रामीण स्कूलों के निर्माण में सरपंचों को जो धन दिया गया था उसमें से अधिकांश सरपंचों ने स्तरहीन काम करवाया 20-25 प्रतिशत ने काम ही नहीं करवाया और पूरा धन ही उकार गए।

प्रदेश में चारों तरफ सरकारी धन की होली खेली जा रही है। दूसरी ओर अधिकांश विभागों में न केवल कर्मचारियों और अधिकारियों की न केवल भारी कमी है। वरन धन के उपयोग दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पत्र नियंत्रण की कही कोई दोहरी व्यवस्था भी न केवल प्रदेश में वरन पूरे देश में ही नहीं है।

आम आदमी की जेब से पैसा निकालने के लिए तो सरकारी तंत्र ने हर कदम भारी व्यवस्था कर रखी है। परंतु उसके कल्याण के लिए अधिकांश योजनाओं का धन सरकारी तंत्र ही पी जाता है।

साप्ताहिक समय माया

केंद्र द्वारा 12 वर्ष की लड़की को सेक्स की छूट, अर्थात

बाल वैश्यावृत्ति चलेगी बाल विवाह नहीं

अमेरिकी इशारे पर देश की युवा पीढ़ी को करेंगे बर्बाद

भारत की पूरी केंद्र सरकार अमेरिकी और युरोपियन एजेंट सोनिया के इशारे पर नाच रही है, यह हर कदम देश के प्रधनमंत्री मनमोहन अपनी हर हरकत से पिछलें वर्ष 7 वर्षों से सिद्ध करता रहा हैं। समय माया अपने शैश्ल काल से ही अमेरिकी षड़यंत्रों और उसकी एजेंट सोनिया द्वारा देश के प्रधानमंत्री को कठ पुतली बन नचाये जाने की सैकड़ों घटनाओं को लगातार प्रकाशित करता रहा हैं, ताकि राष्ट्र की नता के भविष्य की बर्बादी को रोका जा सकें। एडस के नाम पर अमेरिकी कंपनियों द्वारा बनये जाने वाले 10 पैकेट कांडोम को रू 10में बेचने उसकी बिक्री बढ़ाये जाने के लिये स्कूलों में 6वीं से यौन शिक्षा पढ़ाये जाने और भारत की संस्कृति के संयम की विचारकरा के विपरीत स्कूलेमें स्वच्छ यौनाचार के षड़यंत्र के विपरीत राष्ट्रीय मीडिया की विचारधारा के विपरीत भी अकले दम पर विरोध करते आ रहे हैं। ताकि हमारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली पीढ़ी इस स्वच्छंद यौनाचार में उलझने के विपरीत तरीके से अपना शारीरिक मानसिक और बौठिक बिलास ढंग से कर सके, अन्यथा जो हाल युरोपियन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन फ्रांस, आस्ट्रेलिया, जर्मनी व अन्य युरोपिया राष्ट्रों में हो रहा है कि वहां 12-15 वर्ष की हर किशोरी के हाथ में उसकर नव जात से लेकर 2-3 वर्ष का बच्चा होता है, जिसको उसकों गोद में खेलने वाले बच्चे के बाप का नाम तक भी पता नहीं होता कि वह अपने साथ पढ़ने वाले सहपाठी का है, स्कूल बस के ड्राइवर का है, अपने क्लास टीचर का है, पड़ोसी का है, या माँ के पार का है, या पिता या उसके दोस्त का है, स्वाभाविक है इस स्वच्छंद यौनाचार के परिणाम स्व रुप लड़कियों की पढ़ाई लिखाई तो गई एक तरफ बच्चे को पालने में ज्यादा ध्यान देना पड़ता हैं। दूसरी और छात्रों का बयान भी पढ़ाई की अपेक्षा इतने बजे उससे मिलना, उतने बचे उसके साथ करना है मैं ही उलझ कर बर्बाद हो जाता है फिर अमेरिकी राष्ट्र पति बिलक्विंटन जॉज बुस, ओबामा अपने देश की पीढ़ी से अपील करते हैं। तुम भी पढ़कर आगे बढ़ों अन्य था तुम्हारी सारी नौकरियां, धंधे व्यवसाय चीनी और भारतीय पढ़ाक और संयमित बच्चे तुम से छीन लेंगे। पर अब अमेरिकी और युरोपीय विद्यार्थियों को चीनी और भारतीय संयमति जीवन की परिभाषा समझा कर किशोर तय में उन्हें अपने मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास की तरफ मोड़ने में कम से 50 वर्ष चाहिये, दूसरी और अमेरिका और युरोपीय देशों में मॉ-बाप अपनी मौज-मस्ती, खाओं, पीओं और अय्यासी नीति में मस्त रहे, क्लबों, डांस बारों से देर रात लौटे और बच्चे अपने दोस्तों और रहेलियों में मौज मस्ती करे, उदाहरण पूर्ण नीति के चलते सारी किशोर तय जवान होने से पहले ही चहियों में सिमट कर वह गई, तो पढ़ाई क्या खाक होगी, अमेरिका व युरोप समझ चुके है। अपनी बर्बादी के कारणें को अब उनके यहां आ रहे चीनी और भारतीय विद्यार्थियों को रोकने का एक ही तरीका बचा है, किसी किसी प्रकार स्कूलों में ही उनका भविष्य चहियों में बहा दिया जाये ताकि वो वहीं बर्बाद हो जाये और युरोप तरफ मुख न करें इसका सबसे बड़ी बढ़ीयां तरीका है कि स्कूलों के स्वच्छंद यौनाचार को प्रोत्साहित किया जा जाये जिससे उनका शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास रूक जाये और बर्बादी हो, उन्हीं के इशारे पर कपिल सिब्बल ने स्कूलों में 12 वर्षों की लड़कियों को संभोग की छूट देने का मन बना कर मीडिया में प्रसारित करवा दिया हैं। कपिल सिब्बल ने ही पूर्व में ही स्कूलों में यौनाचार की शिक्षा देने का षड़यंत्र भी रचा था पर समय माया ने अपनी इंटरनेट साइटों और समाचार पत्र के माध्यम से इसका लगातार विरोध किया।

दूसरी तरफ परंपरागत हमारे यहां सर्वोच्च न्यायलय से लेकर हमारी केंद्र व पूरे देश की राज्य सरकारें उनके महिला बाल विकास हमारा कानून सब बाल विवाह के विरूद्ध उसे रोकने के लिये सतत प्रयास करते है। जबकि बाल विवाह में 18 वर्ष से कम की लड़की का यदि 20-21 वर्ष या उससे छोटी लड़की से विवाह हो भी जाता है तो अधिकांश समाजों में लड़की का गोना अर्थात माँ घर से पति के घर, लड़की के 18 वर्ष के हो जाने पर ही भेजा जाता है, और कानूनी आवश्यकतायें तो पूरी होती हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ लड़के और लड़की के लिये जीवन साथी की निश्चित के साथ ही साथी के लिये भड़कांव और यहां वहां मुंह मारने की आदत विकसित नहीं हो पाती, (शेष पृष्ठ 2 पर)

जनता को क्रिकेट में उलझाओं राष्ट्र सुरक्षा भूल जाओ

बहुत भारी पड़ेगी चीन घुसपैठ की अनदेखी

अमेरिका कहेगा, तवर स्वीकार करते हैं, चीनी की सीमा में घूसपेठ राष्ट्र में सत्ता संभाले और राष्ट्र के 121 करोड़ लोगों की जेब, जीव पर डकैती डालकर, राष्ट्र के प्राकृतिक व अन्य आय के स्त्रोतों पर कब्जा कर धन बटोरकर स्विस को में जमा करने वाले कांग्रेसी धूर्तों को इसके आगे राष्ट्र की सुरक्ष्ज्ञ की बिलकुल चिंता नहीं हैं। हां चिंता इस बात की आवश्क है,कि सुरक्षा के नाम विदेशों से उपयोग किये, समय व्यत्ति चलन से बाहर हुए हथियारों के कचरे, हवाई जहाजों, पनदुबियों, ब्लाडि मीर गोदी में 1988 से पड़े सड़ रहे गोर्शकोव जैसे युवक लड़ाकू विमान वाहक पोत को जिसकी कीमत रु. 1रु से बढ़ते 2 रु. 12000 करोड़ तक पहुंच गई। कैसे दोगुने से लेकर हजारों गुना ज्यादा कीमत में खरीदकर अंतर की राशि और मोटे कमीशन को कैसे उकार कर दुनिया के किस देश में उद्योगों में बैंकों में चुपचाप छुपाकर सुरक्षित रखा जाये, ऐसी खरीदी की चिंता न केवल पश वरन् विचरा को भी अपने हिस्से की खातिर भरपूर रहती हैं। बेशक राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्ष की चिंता कांग्रेस के धूर्त मक्कार डकैतों को हैं ही नहीं इसके विपरीत विपक्ष में सबसे बड़ा दल, राष्ट्र प्रेमी जन हितेषी और पूर्णतः स्वं देशी होने का नाटक करने वाली भाजपा को भी कदापि नहीं रही, बाकी क्षेत्रीय राजनैतिक दलों की औकात, क्षेत्रीय स्तर तक रहने के साथ ही अगर सत्ता मिल भी जाती हैं तो केवल लूटने चल अचल संपत्तियां बटोरने हजम करने तक ही सीमित होती हैं। पंजाब से लेकर सुदुर दर्शिक भारत की चारों तरफ स्थिति यहीं है। चाहे बसपा, सपा, माकपा, तृणमूल, तेरेपा कोई भी हो। समय माया शेषण काल से चीन की भारतीय सीमाओं में अनवरत गति से चल रही पिछलें 40 वर्षों की घुसपैठ के बारे में अपनी समय माया काम की साइटों और समाचार पगों से लगातार केन्द्रीय शासन और राज्यों की सरकारों को उद्योगों के बहाने जसूसी कर। जानकारी इकट्ठी करने आप्ताधिक संवेदनशील इलाकों में घुसपैठ बनाने के बारे में कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक पश्चिम में बम्बई से लेकर कोलकत्ता, उत्तीपूर्वी असम नागालैंड तक में चारों तरफ की काश्मीर में और उसके उत्तरी क्षेत्र के पास अधीक्रत की जो सीमा से लगती हैं से लेकिर पाकिस्तान तक उसने सड़के चोकियां आदि का तेजी से निर्माण कर लिया हैं। लेह से अरूणाचल, नागालैंड, म्यॉमार तक जो हिस्सा 1962 की लड़ाई में जो कब्जे में किया था 62000 वर्ग मील जो 1 लाख वर्ग किमी है। अतिरिक्त उस 2000 कि.मी. लंबी सीमा 30 से 40 कि.मी. अंदर घुस चुका हैं। वहां पर भी हैलीपेड और सड़कों जाल बिझा चुका हैं, भारत सरकार का अनुसंधान और विश्लेषण विंग अर्थात न केवल वरन् मिलीट्रीइंटेलि जैस भी इस बात से सरकार को चेताता रहा हैं। वरन् हमारे रक्ष्ज्ञ मंत्री ए के एंटनी उन्हें ही शांति है, का राज अलाप कर चीनी शत्रुओं के हौसले बुलंद कर रहें हैं। दूसरी और उसने बुरहानपुर का पानी की दिशा मोड़कर उस पर 24 बांध बनाने की योजना में से 6 पूरे कर लिये 6 पूर्णतः की और हैं। और अगले 6 पर कार्य कर रहा हैं। दूसरी और नेपाल में जो भावसवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के बह पूर्णतः चीनी लोगों का नेपाल रुपातरण हैं। जो नेपाल को अस्थिर करके रखना चाहता हैं, ताकि उस और से भारत में घुसपैठ बनाने और हमला करने में अप्रत्यक्ष तौर से घुसकर भारत की आंतरिक परिस्थितियों का आंकलन कर आक्रमण में सफल हो सकें।

अगर भारत में जातिवादी आंदोलनों और भ्रष्टाचारा की यही दशा और यहीं दिशा रही तो अगले तीन वो भारत पूर्ण तैयारी के साथ हमला करके न केवल कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलकर अलग कर के फिर पाकिस्तान को भी खदेड़कर स्वयं कब्जा करके पंजाब और दिल्ली पर घुसपेठ बना लेगा।

चीनी सेना लाख भारतीय सेना के साथ संयुक्त अभ्यास कने का जो नाटक रही हैं। मात्र भारत की रणनीति मारक क्षमता, उसके हथियारों आदि को जानने के लिए ही कर रही है। वह बस समय के इतजार में है उसे संयुक्त अभ्यास से वह यहीं रोल ही रहा है, कि युद्ध हुआ तो भारत क्या कर सकने में सक्षम हैं। भारत से युद्ध के इस अभ्यास से हमें कितनी हानि पहुंचा पाएगा।

जापान में मार्च में आया 8.9 का भूंकप भी प्राकृतिक नहीं था, यह भी चीन का शक्तिशाली समुद्र की ज्ञापानी सीमा के तल के अंदर किया 200 टीएनटी से ज्यादा शक्ति का परमाणु विस्फोट था जिससे भयानाक भूकंप और सुनामी आई। इस एक भयानक विस्फोटक से जहां जापान फुटकर खिसक गया। वहीं धरती भी अपनी धुरी से 4 खिसक गई। इस विस्फोट से चीन ने न केवल जापान कोवस्- अमेरिका और रूस तक को भी चमका दिया, इसके साथ ही चीन ने एक तीर से कई निशाने साधें। (शेष पृष्ठ 5 पर)

बुरी मुद्रा, अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती हैं-ग्रेसिम

5,10,20,50 के सड़े-कटे-फटे नोट चलन में

स्टेट बैंक के भ्रष्ट अधिकारियों के ढ़ीले प्रबंधन को वूसली से काम पूरे म.प्र. में वर्तमान 5,10,20 और 50 के गले, सड़े, कटे, फटे, नोट चल रहे हैं। हजारों जगह ग्राहकों से दुकानदार और दुकानदार ऐसी कटे फटे मुद्रा स्वीकारने में विवादों का केंद्र बन रहे हैं। आखिर कौन है जिम्मेदार?

पूरे देश में पत्र मुद्रा के चलन और ऐसी सड़ी गल, कटी-फटी पत्र मुद्रा को चलन से बाहर करने और उसके बदले में नई पत्र मुद्रा को चलने में लाने के लिए भा.रिजर्व बैंक जिम्मेदार हैं। जहां रिजर्व बैंक की शाखाये नहीं है भारतीय स्टेट बैंक जिम्मेदार हैं। जहां रिजर्व बैंक की शाखाये नहीं हैं। भारतीय स्टेट बैंक उसके प्रतिनिधि की भूमिका का निर्वाह करता हैं। म.प्र. की राजधानी भोपाल रिजर्व बैंक का होशंगाबाद मार्ग पर प्रादेशिक स्तर का कार्यालय है और उसकी जिम्मेदारी है कि वह प्रदेश में चल रही ऐसी सड़ी-गली कटी-फटी मुद्रा को अपने प्रतिनिधि स्टेट बैंक के माध्यम से बाजार से तत्काल संग्रहित करवाकर नई पत्र मुद्रा को चलन को डाले, इस संदर्भ में म.प्र. का वित्त मंत्रालय भी जनता की सुविधा और पत्रमुद्रा के सुविधा जनक व सुचारू रुप से चलन के पत्र मुद्रा की आसान ग्रहणीयता बनाये रखने हेतु स्वयं भी रिजर्व बैंक को पत्र लिख कर सुचित कर सकता हैं। पर शायद प्रदेश के वित्त मंत्री और उनके प्रधान सचिव व सचिव तक को इसकी जानकारी नहीं होंगी। दूसरा गरीबों के लेन-देन का माध्यम है रु. 5,10,20,50 की पत्र मुद्रा अमीरों और उच्च शासकीय पदों पर बैठे अधिकांश अधिकारियों को रु. 5,10,20,50 नोटों से कोई वास्ता हीं नहीं पड़ता इसलिये उसका ध्यान इसकी और जाता ही नहीं इसलिए कौन और कैसे पत्र लिखें? इसके विपरीत राह कार्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रदेशानिक मुख्यालय भोपाल से स्वयं स्टेट बैंक के प्रबंधक उप महाप्रब्रधक आदि को ही सतत चलने प्रक्रिया से डाला चाहिए था। रु. 1 व 2 के नोटों का चलन समाप्त होकर पूरे प्रदेश-देश में सिक्के आ गए हैं। 5 व 10 के सिक्के अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं है स्वाभाविक है, कि नोटों की ग्रहणीयता बनी हुई है। जिसमें 5 नोटों में 707 नोट पूर्णतः कटे-फटे, सड़े-गले होने के कारण उनमें टेप, पट्टियां चिपकी हैं। और मजबूरी में चलन में लेन-देन के माध्यम हैं। 27 राष्ट्रीयकृत और स्टेट बैंक भी अगर अपने काउंटरों से सिक्के वितरण करने शुरु कर दे तो अधिकतम 15 दिनों में समस्या सुलझायी जा सकती हैं। इसके विपरीत यह एक सामाजिक कार्य हैं। जिसमें राष्ट्रीयकृत और स्टेट बैंक वालों को सीधा कोई लाभ मिलने वाला नहीं, इसलिए यहां पर बैठा मठ्टा निकमा स्टाफ जिसमें अधिकारियों से कर्मचारियों तक सभी शामिल हैं। केवल वह कार्य करना पसंद करते हैं। जिसमें उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ मिले या मिलने की संभावना हो।

जहां तक रिजर्व बैंक का सवाल है, तो वह भी जन कल्याण और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के संचालन की अपेक्षा डकैतों की महाडकैत बन चुका हैं, जिससे पूंजीपति, उद्योगपति, राजनेता और वित्त मंत्रालय अपने लाभ के लिये हांक रहे है। अब उन सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को लूटने की पूरी छूट दे रखी है। चाहे ब्याज की दरों का नियमितीकरण हो, साख नीति का निर्धारण हो ग्राहकों से वसूलने जाने वाले सेवा शुल्क हों, ग्रणों का वितरण हो बड़े और मोटे कर्जों को कमीशन डकार, संदिग्ध और अशेज्य बना कर,घाटे की पूर्ति उपरोक्त, तरीकों से पूरी करने की पूरी आजादी है। जबकि सभी बैंकों में प्रबंध संचालकों, संचालकों से लेकर बाबु चपरासी 30 प्रतिशत अधिकारी भ्रष्ट जालसाज हो चुके हैं। जो उदासीन खातों से लेकर ग्राहकों के चेकों संग्रहण की रकम तक डकार जाते हैं। जब ग्राहक पूछताछ करते है तो हरामखोरों जालसाजों की फौज मारापीटी पर उतारू हो जाती है तो फिर कैसे उम्मीद की जा सकती है, कि सड़े-गले, कटे-फटे नोटों का संग्रहित कर नये नोट चलन में डाले जायेंगे व जनता की परेशानी दूर की जाएगी।

स्वामित्वाधिकारी, प्रधान संपादक एवं प्रकाशक अजमेरा एस.पी. कुमार के लिए मीडिया वर्ल्ड कम्यु/ 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर के लिए नवनीत प्रिंटर्स जेल रोड, इंदौर से मुद्रित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9074551045, इंदौर कार्यालयः 0731- 2530859, मो. 9300755803